हिमाचल प्रदेश विधान सभा

विधान सभा की बैठक सोमवार, दिनांक 17 मार्च, 2025 को माननीय अध्यक्ष, श्री कुलदीप सिंह पठानिया की अध्यक्षता में कौंसिल चैम्बर, शिमला-171004 में 11.00 बजे पूर्वाह्न आरम्भ हुई।

17-03-2025/1100/वाई.के.-एन.जी/1

बजट अनुमान वित्तीय वर्ष 2025-26

अध्यक्ष : अब मैं माननीय मुख्य मंत्री, श्री सुखविन्दर सिंह सुक्खू जी से अनुरोध करता हूं कि वे वित्तीय वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमानों और वास्तविक वित्तीय विवरण को सदन में प्रस्तुत करें।

मुख्य मंत्री : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति से मैं वर्ष 2025-2026 के बजट अनुमानों को प्रस्तुत करता हूं :-

मैं एक शेर के साथ शुरू करना चाहूंगा :-

"न गिराया किसी को कभी, न खुद को उछाला,
कटा जिंदगी का सफर धीरे-धीरे।
जहां आप पहुंचे छलांग लगा लगा कर,
मैं भी पहुंचा वहीं मगर धीरे-धीरे।"

1. यह हमारी सरकार का तीसरा बजट है। यह बजट प्रदेश की आर्थिक स्थिति को पटरी पर लाने हेतु सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों पर केन्द्रित है। बजट में सभी वर्गों के सर्वांगीण विकास एवं उनके जीवन को सुगम बनाने पर बल दिया गया है।

2. अध्यक्ष महोदय, 11 दिसम्बर, 2022 को कांग्रेस सरकार को सत्ता की बागडोर सम्भालते ही नाजुक वित्तीय स्थिति, पनपते Mining Mafia, पूर्व सरकार द्वारा लापरवाही से की गई भरपूर फिजूलखर्ची जैसी चुनौतियों का सामना करना पड़ा। पिछली सरकार द्वारा कई सरकारी भवनों तथा अन्य पूंजीगत कार्यों का बिना बजटीय प्रावधानों के ही निर्माण किया गया और बिना ज़रूरत के संस्थानों को खोला गया। इसका परिणाम यह हुआ कि प्रदेश भर में Civil Contractors के प्रति करोड़ों रुपये की देनदारियां खड़ी हो गई।

17-03-2025/1100/वाई.के.-एन.जी/2

एक हज़ार करोड़ रूपये से ज्यादा राशि के अधिकांश भवन बिना किसी विवेक के बनाए गए जो कि आज तक किसी भी काम में नहीं लाए जा सके हैं। इनके निर्माण के लिए Centrally Sponsored Schemes तथा Externally Aided Projects के अन्तर्गत मिलने वाली राशि का दुरुपयोग किया गया जिसके परिणाम कई प्रकार की चुनौतियों के रूप में वर्तमान सरकार के सामने आए।

3. आने वाला काल गम्भीर संकट व Transition का है। वैश्विक व्यापार युद्ध, टैरिफ वार, गिरती हुई अर्थव्यवस्थाएं, बदलते मूल्य, उभरती हुई नई Geo Political व सामरिक चुनौतियां तथा उनका अर्थव्यवस्था पर दुष्प्रभाव। देश व प्रदेश दोनों इससे अछूते नहीं हैं। देश के मार्किट व देश की अर्थव्यवस्था में मंदी की दस्तक सुनाई दे रही है। मुझे देश की आर्थिक स्थिति पर भी अपनी चिंता व्यक्त करनी आवश्यक लगती है। उद्योगों की वृद्धि दर धीमी हो रही है, व्यापार पर असर पड़ा है, रोज़गार के अवसर भी घट रहे हैं और निजी खपत में कमी के कारण घरेलू मांग में भी कमी आ रही है। FIIs (Foreign Institutional Investors) की भारतीय शेयर बाजार में भारी बिकवाली से आ रही गिरावट से Retail Investors का लाखों-करोड़ों का नुकसान हो गया है। RBI को भी मुद्रास्फीति और कमजोर रुपये के चलते नीतिगत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है और इसका असर महंगाई पर भी पड़ रहा है। कुछ के लिए यह केवल अस्थायी ठहराव है जबकि मैं इसे दीर्घकालीन चुनौती के रूप में देख रहा हूं।

पैरा संख्या-4......श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

17.03.2025/1105/ वाई0के0/पी0बी0 /-1

4. इन सब चुनौतियों के बीच हमारा प्रदेश और भी अधिक प्रभावित हुआ है। एक और जो हमें देय है वह मिल नहीं रहा- जैसे पी0डी0एन0ए0, बी0बी0एम0बी0 का शेयर। एन0पी0एस0 शेयर के रूप में राज्य सरकार और सरकारी कर्मचारियों का लगभग 9,000 करोड़ रुपये का फंड केन्द्र (एन0एस0डी0एल0) से लेने शेष है। जी0एस0टी0 कंपनसेशन पहले ही बंद है और दूसरी ओर अब रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट (आर0डी0जी0) की टेपरिंग से साल दर साल की गिरावट जारी है।

5. वैट के स्थान पर जी0एस0टी0 लागू करके व जी0एस0टी0 कंपनसेशन देने के बाद भी राज्य सरकार को वर्ष 2023-24 तक कुल 9,478 करोड़ रुपये का राजस्व घाटा हुआ है। आर0डी0जी0 के मामले में भी ऐसा ही हुआ है और मेरी नज़र में आर0डी0जी0 कोई ग्रांट नहीं है। आर0डी0जी0 एक प्रकार का Post Devolution Compensation है, उन प्रदेशों के लिए जो मूलतः रेवेन्यू डेफिसिट इकाइयां हैं तथा जिनका गठन किसी आर्थिक स्वायत्तता या आत्मनिर्भरता के आधार पर नहीं अपितु इन क्षेत्रों की जन-आकांक्षाओं को पूरा करने के लिए हुआ है। हिमाचल प्रदेश एवं अन्य पहाड़ी राज्य इसलिए स्पेशल केटेगरी के राज्य माने गए।

6. योजना आयोग के बंद होने व पिछले 10 सालों में भारत सरकार द्वारा हर योजना व वित्तीय सहायता में तरह-तरह की शर्तें लगातार लगाए जाने के कारण हम आर्थिक दृष्टि से उपेक्षित होते जा रहे हैं। सदन में माननीय नेता प्रतिपक्ष इस बात से पूर्णतः अवगत है कि पंद्रहवें वित्त आयोग की सिफारिशों के कारण वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 के दौरान आर0डी0जी0 पिछले पांच वर्षों में तेजी से गिरी है।

7. 14वें वित्त आयोग की सिफारिश पर पांच वर्षों 2015-16 से वर्ष 2019-20 के लिए आर0डी0जी0 के रूप में हमें 40,624 करोड़ रुपये मिले। अर्थात इन पांच वर्षों में हर वर्ष में हमें लगभग 8,000 करोड़ रुपये की आर0डी0जी0 मिली। 14वें वित्तायोग की तुलना में 15वें वित्त आयोग ने प्रदेश को मिलने वाली आर0डी0जी0 40,624 करोड़ रुपये से घट कर

37,199 करोड़ रुपये हो गई, जोकि यदि मुद्रस्फिति को ध्यान में रखें तो यह आज 30,000 करोड़ रुपये के आस-पास बनती है। सदन को इस बात का भी आश्चर्य होगा कि पंद्रहवें वित्त आयोग में कुछ ऐसे कारणों से जो बिल्कुल तर्कसंगत नहीं हैं, वर्ष 2021-22 से वर्ष 2025-26 तक लगातार हर वर्ष आर0डी0जी0 कम की गई।

8. वर्ष 2021-22 में यह ग्रांट 10,949 करोड़ रुपये थी, वर्ष 2022-23 में यह घट कर 9,377 करोड़ रुपये हो गई। जबकि वर्ष 2023-24 में यह फिर गिरी और 8,058 करोड़ रुपये रह गई है। इस वित्तीय वर्ष 2024-25 में आर0डी0जी0 घट कर 6,258 करोड़ रुपये हो गई और अब आने वाले साल 2025-26 में यह मात्र 3,257 करोड़ रुपये है। 10,249 करोड़ रुपये से 3,257 करोड़ रुपये तक आर0डी0जी0 का गिरना प्रदेश की अर्थव्यवस्था को कितना अधिक प्रभावित करेगा आप भली-भांति समझ सकते हैं।

9. वर्ष 2025-26 का साल हमारे प्रदेश की अर्थव्यवस्था के लिए मेरी नज़र में पिछले कई दशकों में सबसे चुनौतीपूर्ण साल है। लेकिन मेरी सरकार प्रतिबद्ध है कि हम इस चुनौती को प्रदेश की जनता, कर्मचारी वर्ग तथा सदन के साथ मिलकर स्वीकार करेंगे और भारत सरकार के समक्ष प्रदेश के साथ अन्याय न हो इस संबंध में अपना पक्ष मज़बूती के साथ रखेंगे।

10 श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

17.03.2025/1110/A.P/A.G/01

10. माननीय अक्ष्यक्ष महोदय, वर्ष 2023 में मॉनसून के दौरान राज्य को भारी तबाही का सामना करना पड़ा जोकि राज्य के इतिहास की एक सबसे बड़ी तबाही थी जिसमें हज़ारों घर तबाह हुए तथा बहुमूल्य जानें गईं। हमने अपने संसाधनों से 4 हज़ार 500 करोड़ का आपदा राहत पैकेज़ दिया। हम केन्द्र सरकार का धन्यवाद करते हैं, जिन्होंने Central PDNA टीम भेजी और प्रदेश के अधिकारियों के साथ मिलकर इसका आकलन किया। इस आकलन में 9 हज़ार 42 करोड़ रुपये की पी0डी0एन0ए0 रिपोर्ट केन्द्र को नवंबर, 2023 में

भेजी गई। अगस्त, 2024 में पी0डी0एन0ए0 के मानक अधिसूचित होने के बाद राज्य सरकार ने केंद्र सरकार से नवम्बर, 2024 से फरवरी, 2025 के बीच धन की मांग बारे संपर्क बनाए रखा परन्तु फिर भी अभी तक कोई वित्तीय सहायता नहीं मिली है। आशा है कि केन्द्र सरकार, प्रदेश के हित में यह राशि शीघ्र ही जारी करेगा।

11. हमारी सरकार ने सभी चुनौतियों के चलते हिमाचल प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का संकल्प लिया है। जहां आवश्यकता थी, वर्षों से चली आ रही व्यवस्थाओं में परिर्वतन किया। कुछ बदलावों का भरपूर विरोध भी हुआ तथा विपक्ष द्वारा तंज भी कसे गये। इन सबकी परवाह न करते हुए हमारी सरकार प्रदेश के विकास के संकल्प को साकार करने के पथ पर अडिग रही और व्यवस्था परिवर्तन के सफ़र को जारी रखा गया। गत दो वर्षों में प्राकृतिक आपदाओं के दौरान सरकार द्वारा किये कार्य इसका प्रत्यक्ष उदाहरण है। हम हिमाचल प्रदेश में विकास कार्यों को न तो रुकने देंगे, न ही उनमें कोई कमी आने देगें। बल्कि हमने जो प्रयास किये हैं, उनके कारण विकास के कार्यों में अभूतपूर्व तेजी देखी गई है। हमने न सिर्फ टेंडर की प्रक्रिया को सरल किया बल्कि लगातार मूल्यांकन के माध्यम से बड़ी परियोजनाओं को निश्चित समय सीमा में धरातल पर उतारने की पहल की है। पिछले दो वर्षों में लिये गए निर्णयों के सुखद परिणाम आज सामने आने शुरू हो गए हैं।

12. पिछली सरकार द्वारा Resource Mobilization की ओर कोई विशेष ध्यान नहीं दिया गया जिससे राज्य की कर्ज पर निर्भरता बढ़ी है। परन्तु वर्तमान सरकार द्वारा इस दिशा में विशेष कदम उठाए गए हैं। हमारे प्रयासों के परिणाम प्रथम वर्ष (2023-24) में ही आने

17.03.2025/1110/A.P/A.G/2

शुरू हो गये थे। राज्य के सकल घरेलू उत्पाद की दर जो कि वर्ष 2022-23 में 6.89 प्रतिशत थी वर्ष 2023-24 में बढ़कर 7.03 प्रतिशत हो गई। राज्य के अपने राजस्व प्राप्ति का कुल राजस्व प्राप्ति में हिस्सा वर्ष 2022-23 में 35.37 प्रतिशत से बढ़कर वर्ष 2023-24 में 37.92 प्रतिशत हो गया है। इसी प्रकार से राज्य के अपने राजस्व और कुल खर्चे की दर जोकि वर्ष 2022-23 में 24.99 प्रतिशत थी, वर्ष 2023-24 में बढ़कर 27.54 प्रतिशत हो गई है।

उल्लेखनीय है कि वर्ष 2022-23 की तुलना में वर्ष 2023-24 में विभिन्न मदों की आय में संतोषजनक वृद्धि दर्ज की गई है। विक्रय एवं व्यापार इत्यादि पर VAT में 27.98 प्रतिशत, State Excise में 21.48 प्रतिशत, बिजली में 16.74 प्रतिशत, Non & Ferrous Mining and Metallurgical Industries 15.85 प्रतिशत, Taxes on Vehicles 15.78 प्रतिशत व स्टाम्प तथा Stamps and Registration Fees में 10.44 प्रतिशत वृद्धि हुई है। इसके अतिरिक्त वर्तमान सरकार द्वारा बिजली के उपयोग पर दी जाने वाली सब्सिडी का भी युक्तिकरण किया गया है। जिसके तहत साधन सम्पन्न लोगों द्वारा स्वेच्छा से सब्सिडी को छोड़ा जा रहा है और साथ ही इससे सरकार के संसाधनों पर दूरगामी प्रभाव पड़ेगा। अध्यक्ष महोदय, मुझे आपके माध्यम से इस सदन को सूचित करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि वित्तीय वर्ष 2023-24 में State Excise Duty और VAT में 867 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है तथा 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपये की वृद्धि होने की संभावना है। यह वृद्धि हमारी सरकार द्वारा एक्साइज पॉलिसी में किये गए बदलावों के द्वारा ही संभव हो पाई है। राज्य की आत्मनिर्भरता की ओर यह एक महत्वपूर्ण कदम है।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी---

17.03.2025/1115/AT/ऐ0जी0 /1

13.हमारी सरकार ने उपकर के माध्यम से भी आय बढ़ाने का प्रयास किया गया है। फलस्वरूप, वर्ष 2023-24 में शराब पर लगाए गए उपकर से 145 करोड़ रूपये अर्जित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त शराब पर लगाए गए उपकर को छोड़ कर वर्ष 2024-25 से वर्ष 2025-26 के दौरान विभिन्न उपकरों से 126 करोड रूपये की अतिरिक्त आय अनुमानित है।

14. हम सभी को मिलकर और अधिक प्रयास करने होंगे ताकि Resource Mobilization बढ़ाई जा सके। मुझे इस सदन के पक्ष एवं विपक्ष, सभी सदस्यों से यह आग्रह करना है कि वे मुझे अपने बहुमूल्य सुझाव दें।

15. अध्यक्ष महोदय, मैं आज सदन में पहली बार राज्य द्वारा लिए जा रहे Loans व इनकी Repayment की वास्तविकता से लोगों को अवगत करवाना चाहता हूं, सदन को अवगत करवाना चाहता हूं क्योंकि इस पर चर्चा करना जरूरी लगता है। महोदय, सरकारें आती हैं, जाती हैं, परन्तु मुझे यह कहना है कि राज्य सरकार अपने राजकोषीय घाटे को एक निश्चित सीमा के भीतर बनाए रखने के लिए बाध्य है, जो राज्य सरकार के वित्तीय उत्तरदायित्व और बजट प्रबन्धन अधिनियम (FRBM) के अनुसार 2024-25 और 2025-26 के लिए क्रमशः 3.5 और 3 प्रतिशत है। राज्य सरकार तब तक धन उधार नहीं ले सकती जब तक कि उसे भारत सरकार द्वारा भारत के संविधान के अनुच्छेद 293 (3) के तहत अधिकृत नहीं किया गया हो। 2024-25 के लिए राज्य का सामान्य उधार लेना भारत सरकार द्वारा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का 3 प्रतिशत तक सीमित कर दिया गया है और इसे 6 हजार 551 करोड़ रुपये पर Cap किया गया है। इसी तरह भारत सरकार वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए शुद्ध ऋण सीमा की गणना करेगी और उचित समय पर राज्य सरकार को सूचित करेगी। जो इस वर्ष के ऋण आना है, उसके लिए वे गणना करके बताएंगे। किसी भी वर्ष में उधारी सीमा का अधिक उपयोग होने की स्थिति में, इसे केन्द्र सरकार द्वारा अगले वर्ष की सीमा से काट दिया जाता है। यहां मै यह भी स्पष्ट कर देना चाहता हैं कि राज्य सरकार किसी भी Source से कोई भी ऋण केन्द्र सरकार की अनुमति के बिना नहीं ले सकती। इसलिए राज्य सरकार के पास निर्धारित ऋण सीमा से परे जाने का कोई विकल्प नहीं है। जब वर्तमान सरकार सता में आई तो 31 मार्च, 2023 को पिछली सरकार से 76 हज़ार 185 करोड़ रूपये के ऋण विरासत में मिले जिसका भुगतान और ब्याज की वापसी हमारी सरकार को करनी पड़ रही है। हमें पिछली सरकार द्वारा लिए गए ऋण पर 12 हज़ार 266 करोड़ रूपये का ब्याज भुगतान तथा 8 हज़ार 87 करोड़ रूपये की ऋण वापसी करनी पड़ी। इस तरह से हमारी सरकार के पास 29 हजार 46 करोड़ रूपये के लोन में से मात्र 8 हजार 693 करोड़ रूपये ही विकास कार्यों के लिए बचे। स्पष्ट है कि हमने जो लोन लिया उसका 70 प्रतिशत पुराने लोन का मूलधन और ब्याज लौटाने में चला गया।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

17.03.2025/1120/md/AS/1

माननीय मुख्य मंत्री----जारी

16. अध्यक्ष महोदय, अब मैं राष्ट्रीय व प्रदेश स्तर के विकास के आंकड़े प्रस्तुत करता हूँः-

2024-25 के दौरान भारतीय अर्थव्यवस्था के 6.4 प्रतिशत् की दर से बढ़ने का अनुमान है। कृषि क्षेत्र एवं सम्बद्ध क्षेत्रों में 3.8 प्रतिशत् की वृद्धि दर अनुमानित है। वित्तीय वर्ष 2024-2025 के अग्रिम अनुमानों के अनुसार देश की प्रति व्यक्ति आय दो लाख 1 सौ 62 रूपये अनुमानित है।

> अध्यक्ष महोदय, सकल राज्य घरेलू उत्पाद प्रदेश की आर्थिक वृद्धि को मापने का प्रमुख सूचक है। वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश की अर्थव्यवस्था की वृद्धि दर 6.7 प्रतिशत् रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के दौरान प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय गत वर्ष की तुलना में 9.6 प्रतिशत की वृद्धि के साथ 2 लाख 57 हजार 212 रुपये रहने का अनुमान है, जोकि देश की प्रति व्यक्ति आय से 57 हजार 50 रूपये अधिक है। 2024-25 में राज्य का सकल घरेलू उत्पाद 2 लाख 32 हजार 185 करोड़ रुपये रहने का अनुमान है।

प्रदेश अर्थव्यवस्था

17. मेरी सरकार हिमाचल प्रदेश को "Natural" तथा "Green" प्रदेश बनाने के लिए कृत संकल्प है। माननीय सदन के सभी सदस्यों का ध्यान में "Natural" तथा "Green" इन दो शब्दों की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

18. "Natural" शब्द एक ओर हमारे प्रदेश की प्राकृतिक सुन्दरता को रेखांकित करता है वहीं दूसरी ओर यह विकास तथा पर्यावरण के प्रति मेरी सरकार के दृष्टिकोण को भी इन्गित करता है। चाहे कृषि विभाग हो या बागवानी, चाहे पशुपालन हो या वन विभाग, चाहे उद्योग हो या परिवहन, हमारा यही प्रयास है कि हमारे विकास का दर्शन व उसके मूल्य Natural/ प्राकृतिक हों। हम Chemicals, Fertilizers, Pesticides तथा अन्य प्रदूषण फैलाने वाली वस्तुओं के प्रयोग को कम करना चाहते हैं। जलवायु परिवर्तन की लड़ाई में भी हम पूर्ण सहयोग करना चाहते हैं।

17.03.2025/1120/md/AS/2

19. मैं अक्सर यह कहता हूँ कि हिमाचल प्रदेश Lungs of North India है। हम अपने वनों की रक्षा करते है, Ecology व पर्यावरण का संतुलन रखते हैं। ये सब एक तरह से हमारी Ecological Services हैं जिन्हें हम मिटटी, पानी, शुद्ध वायु, अच्छी जलवायु के रूप में देश को देते हैं। अगर मैं हिमाचल प्रदेश की Ecological Services के देश के पर्यावरण में योगदान को देखूं तो एक अनुमान के अनुसार वह प्रतिवर्ष लगभग 90 हजार करोड रूपये बनेगा। सरकार इसका एक तकनीकी व वैज्ञानिक मूल्यांकन शीघ्र करवा रही है। दुःख है तो इस बात का कि अभी तक हमारी इस Opportunity Cost की कोई भरपाई नहीं हो पाई है। इसी लिए मेरी सरकार यह प्रयास कर रही है कि हिमाचल प्रदेश के इस बहुमूल्य योगदान को हम भारत सरकार के16 वें वित्तायोग के समक्ष दृढ़ता से रखें।

20. कृषि बागवानी तथा अन्य विभागों के बारे में जब आगे उल्लेख आएगा तो प्राकृतिक/Natural दिशा में किए प्रयास आपके समक्ष और अधिक स्पष्ट हो जाएंगे ।

21. अब मैं Green Himachal के विषय में संक्षेप में बताना चाहता हूँ। 17 मार्च 2023 को इस माननीय सदन में प्रस्तुत अपने पहले बजट में मैंने कहा था कि हमारी सरकार 31 मार्च 2026 तक प्रदेश को Green Energy State के रूप में विकसित करने के लिए प्रभावी कदम उठाएगी। मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम इस लक्ष्य को प्राप्त करेंगे।

22. मैं दो-तीन बातों से "Green Energy State" वाले Concept को स्पष्ट करना चाहता हूँ। देखिए अगर हम प्रदेश की ऊर्जा की सारी खपत के लिए, जो लगभग 14 हज़ार मिलियन यूनिट है, का लगभग 90 प्रतिशत Renewable/Green Energy स्रोतों का प्रयोग करें तो हम एक "ग्रीन स्टेट" कहला पाएंगे। इसका सीधा लाभ प्रदेश में हो रहे औद्यौगिक व कृषि के उत्पादन को मिलेगा। हम इस ओर तेजी से बढ़ रहे हैं। धीरे-धीरे हमारी ऊर्जा खपत अब मूलतः Hydro व Solar स्त्रोतों पर आधारित हो गई है। प्रदेश में हमारी सरकार के इस कार्यकाल में सौर ऊर्जा में जितनी वृद्धि हुई है वह अतुलनीय है - इतनी कभी नहीं हुई। इस बारे में विस्तृत उल्लेख आगे होगा।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

17.03.2025/1125/केएस/एएस/1

23. Green State का एक दूसरा महत्वपूर्ण भाग है परिवहन (Transport) का क्षेत्र। मैं सदन को यह बताना चाहता हूँ कि Green House Gases के Emission जिससे जलवायु पर दुष्प्रभाव पड़ता है, का लगभग 16 से 20 प्रतिशत परिवहन क्षेत्र से आता है। अगर हमें Natural व Green हिमाचल की ओर बढ़ना है तो आवश्यक है कि हम परिवहन के क्षेत्र में e-Vehicles व उसके लिए Enabling Infrastructure पर बल दें।

24. चरण बद्ध रूप से हम HRTC के Fleet में e-buses को बढ़ावा दे रहे हैं। चिन्हित राष्ट्रीय राजमार्गों पर जैसा मैंने सदन में वायदा किया था कि चार्जिंग स्टेशन तथा Infrastructure बनाया जाएगा जोकि बनाया गया है और बनाया भी जा रहा है। सरकारी विभागों में भी ई-गाड़ियों का प्रयोग शुरू कर दिया गया है। टैक्सियों के लिए भी विशेष अनुदान दिया जाएगा ताकि प्रदेश में ई-वाहनों का प्रयोग बढ़े। इसकी चर्चा मैं बजट भाषण में आगे भी करूंगा।

25. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना हमारी प्राथमिकता है। सरकार ग्रामीण आजीविका को स्थानीय संसाधनों के साथ जोड़कर लोगों के जीवन स्तर में सुधार के लिए काम कर रही है। मैं इस दिशा में सरकार द्वारा उठाए गए कदमों का उल्लेख करना चाहूँगाः-

> प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए प्रदेश में पहली बार दूध, प्राकृतिक गेहूं और मक्की के लिए Minimum Support Price की घोषणा की गई है।

> सेब, आम और अन्य फलों की खेती को बढ़ावा देने, उच्च मूल्यों वाले फूलों की संरक्षित खेती करने व मौसम आधारित फसल बीमा योजना इत्यादि के माध्यम से किसानों/बागवानों को लाभ दिया जा रहा है।

> हमारी सरकार का यह प्रयास है कि हिमाचल प्रदेश की ग्रामीण अर्थव्यवस्था को नई ऊंचाइयों तक पहुंचाया जाए।

26. ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास में महिलाओं की भागीदारी सुनिश्चित करने के लिए स्वयं सहायता समूहों द्वारा तैयार किए गए Products की बिकी के लिए एक ई-कॉमर्स वैबसाईट "himira.co.in" का आरम्भ किया गया है। अन्य उत्पादों के साथ-साथ

17.03.2025/1125/केएस/एएस/2

प्राकृतिक रूप से तैयार मक्की का आटा इस प्लेटफॉर्म पर "हिम भोग" Brand के नाम से बिकी के लिए उपलब्ध है। Natual Farming कर रहे एक लाख 58 हज़ार 785 किसानों को प्रमाणित किया गया है। आने वाले समय में हमारी सरकार द्वारा बाजार को ग्रामीण उद्यमियों (Entrepreneurs) के द्वार पर लाने के प्रयास को और भी प्रभावी रूप से धरातल पर उतारा जाएगा।

27. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा समाज के सभी वर्गों के कल्याण हेतु अनेक कल्याणकारी योजनाएं चलाई जा रही है। वर्तमान में प्रदेश में 8 पैन्शन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्यरत हैं। "इन्दिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि योजना" के तहत महिलाओं को आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। "स्वर्ण जयंती आश्रय योजना" में अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को मकान निर्माण के लिए आर्थिक सहायता दी जा रही है। मेरी सरकार की Flagship Scheme "मुख्यमन्त्री सुख आश्रय योजना" के अन्तर्गत सरकार की ओर से शिमला जिला से 22 Children of the State के पहले दल को 13 दिनों के शैक्षणिक भ्रमण (Educational Tour) पर देश के विभिन्न भागों में ले जाया गया। तदोपरान्त बिलासपुर, हमीरपुर, मण्डी तथा सिरमौर जिलों से भी कुल ऐसे 77 बच्चों को देश के विभिन्न भागों में शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया गया। इसी पहल को आगे बढ़ाते हुए आगामी वित्त वर्ष में भी अन्य जिलों के बच्चों को शैक्षणिक भ्रमण के लिए ले जाया जाएगा। साथ ही, उनकी उच्च शिक्षा और कौशल विकास में सहयोग के लिए "मुख्यमंत्री सुख-आश्रय कोष" की स्थापना की गई है, जिसमें स्वैच्छिक योगदान और CSR फण्ड भी प्राप्त किए जा सकते हैं। उपरोक्त के अतिरिक्त वित्तीय वर्ष 2024-25 में इस योजना के अन्तर्गत लगभग चार हज़ार से अधिक बच्चों को प्रमुख भारतीय त्यौहारों के लिए त्यौहार भत्ता एवं अनुदान, सामाजिक सुरक्षा, वस्त्र भत्ता, पोषण अनुदान, मिश्रित अनुदान, उच्च शिक्षा और कौशल विकास, स्टार्ट-अप

अनुदान के रूप में 14 करोड़ 77 लाख 02 हज़ार का व्यय किया गया। इसके अतिरिक्त जिला बिलासपुर और हमीरपुर में 2 Children of the State को भूमि आवंटित की गई व निर्माण हेतु राशि भी प्रदान की गई।

अ0व0 द्वारा जारी---

17.03.2025/1130/av/dc/1

मुख्य मंत्री क्रमागत----------

28. अध्यक्ष महोदय, जैसा कि मैंने पहले भी कहा है कि मैं हिमाचल प्रदेश को Natural, Green State, Lungs of the North India के रूप में देखता हूं और यदि मैं इसे पर्यटन से जोड़ूं तो यहां देश-विदेश से पर्यटक साफ वातावरण और प्रकृति का अनुभव करने आते हैं। इसी के चलते हमारी सरकार राज्य में पर्यटन को प्रोत्साहित करने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठा रही है। इस बजट में वेलनेस सेंटर, आइस स्केटिंग रिंक, और राफ्टिंग सेंटर जैसी सुविधाओं को विकसित करने का प्रस्ताव है। साथ ही, होम स्टे को प्रोत्साहित करने के लिए Interest Subvention Scheme लाई जा रही है। राज्य के विभिन्न हिस्सों में हेलीपैड बनाने की योजनाओं के साथ-साथ कांगड़ा हवाई अड्डे का विस्तार भी हमारी प्राथमिकताओं में शामिल है। जिससे यहां बड़े विमानों की Landing सम्भव हो सकेगी और पर्यटकों को आसान और तेज परिवहन सुविधा मिल सकेगी तथा पर्यटकों की संख्या में वृद्धि होगी। इसके अलावा सरकार धार्मिक पर्यटन, चाय पर्यटन (Tea Tourism) और प्रदेश के अनछुए क्षेत्रों को पर्यटन की दृष्टि से विकसित करने पर कार्य कर रही है। हमें विश्वास है कि इन सभी प्रयासों से राज्य में पर्यटकों की संख्या में अप्रत्याशित वृद्धि होगी, रोज़गार के अवसर बढ़ेंगे तथा राज्य की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होगी।

पशुपालन

29. महोदय, हमारी सरकार पशु पालन के क्षेत्र में महत्वाकांक्षी योजनाएं लागू कर रही है। वर्ष 2025-2026 में पशु चिकित्सा, प्रजनन, रोग प्रतिरोधक टीकाकरण, विस्तार सुविधाओं इत्यादि के अतिरिक्त कई नए पग उठाए जाने का प्रस्ताव है।

30. सरकार द्वारा जिला सोलन के दाड़लाघाट में 4.50 करोड़ रुपये की लागत से बन रहा कृत्रिम गर्भाधान प्रशिक्षण संस्थान क्रियाशील कर दिया जाएगा।

31. भेड़ और बकरी पालकों के कल्याण के लिए एक विस्तृत एवं प्रभावी कार्य योजना लागू की जाएगी। घुमन्तू भेड़-बकरी पालकों के Migratory Routes को Map करके GPS से Track किया जाएगा।

32. Wool Federation के माध्यम से ऊन के सही रख-रखाव हेतु 450 वर्ग मीटर आकार के स्टोर का निर्माण वूल ग्रेडिंग-कम-मार्केटिंग सेंटर बनूरी, पालमपुर में किया जा रहा है।

17.03.2025/1130/av/dc/2

इसके अतिरिक्त राज्य में भेड़ की ऊन की निर्बाध खरीद हेतु 50 लाख रूपये के Revolving Fund का प्रावधान किया जाएगा।

33. मैं प्रदेश की पंजीकृत दूध Societies के सुदृढ़ीकरण के लिए इन्हें मिलने वाली Freight Subsidy को 1.5 रुपये प्रति लीटर से बढ़ाकर 3 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं।

34. Milkfed में दूध Procurement के कार्य को पूर्णतः डिजिटल किया जाएगा। Technology की मदद से किसानों को मिलने वाली सभी जानकारी मोबाइल पर ही उपलब्ध करवा दी जाएगी। इसके लिए Milkfed में ERP System को लागू किया जाएगा। साथ ही सभी पशुओं को भी Life Cycle Approach के अन्तर्गत एक Integrated Digital Platform पर लाया जाएगा।

35. वित्तीय वर्ष 2025-2026 में डेयरी विकास के लिए कांगड़ा, मण्डी, शिमला, सिरमौर और सोलन जिलों के लिए लगभग 10,73,27000/- रुपये खर्च किए जाएंगे। परियोजना के अन्तर्गत मुख्य गतिविधियों में Milk Processing Plant डगवार, कांगड़ा में नई केंद्रीय परीक्षण प्रयोगशाला की स्थापना, दुग्ध उत्पादकों और तकनीकी व्यक्तियों को प्रशिक्षण, और दूध खरीद इकाइयों का डिजिटलीकरण शामिल है।

36. राज्य में डेयरी गतिविधियों के सुधार हेतु नाहन, नालागढ़, मौहल, रोहड़ू में 20 हज़ार एलपीडी क्षमता के 4 नए संयन्त्र और 2 Milk Chilling Centre (MCC) ऊना और हमीरपुर में शुरू किए जाएंगे।

37. मैं आगामी वित्त वर्ष के लिए गाय के दूध की खरीद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य को 45 रुपये से बढ़ाकर 51 रुपये तथा भैंस के दूध को 55 रुपये से बढ़ाकर 61 रुपये प्रति लीटर करने की घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान या कोई Society 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित Notified Collection Centre पर दूध स्वयं ले जाते हैं तो उन्हें 2 रुपए प्रति लीटर की दर से Transport Subsidy भी दी जाएगी। इस प्रकार बेचे गए दूध में किसान को आठ रुपये प्रति लीटर अतिरिक्त दिए जाएंगे। मैंने पिछली बार जो 13 रुपये बढ़ाए थे उसमें 8 रुपये की और वृद्धि कर रहा हूं ताकि ग्रामीण अर्थ-व्यवस्था और मजबूत हो।

टी सी द्वारा जारी

17.03.2025/1135/टी0सी0वी0/डी0सी0-1
मुख्य मंत्री .... जारी

पशुपालन के क्षेत्र में कुल 673 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

कृषि

38. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के लगभग दो तिहाई जनसंख्या प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कृषि से जुड़ी है। बेहतर प्रबंधन के लिए सरकार द्वारा वर्तमान में चल रही आठ योजनाओं को **मुख्य मंत्री कृषि संवर्धन योजना एवं मुख्य मंत्री कृषि उत्पादन संरक्षण योजना** के रूप में एकीकृत किया गया है। वर्ष 2025-26 के दौरान उक्त योजनाओं के अंतर्गत 35 करोड़ रुपये व्यय किए जाने का प्रस्ताव है।

39. प्रदेश के ग्रामीण अर्थव्यवस्था के मुख्य स्तंभ, किसानों के हित में सरकार "**Agriculutre Loan Interest Subvention Scheme**" लाएगी। जिसके तहत ऐसे किसानों जिनकी जमीन नीलामी की कगार पर आ गई हो, उनके द्वारा लिए गए तीन लाख रुपये

कृषि लोन को चुकाने हेतु, सरकार बैंकों के माध्यम से वन टाइम सेटलमेंट पॉलिसी लाएगी। इस पॉलिसी के अंतर्गत मूलधन पर लगने वाले ब्याज का 50 प्रतिशत हिस्से का वहन द्वारा सरकार किया जाएगा। इस योजना के अंतर्गत 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों कुछ लोग मुझसे यहां विधान सभा में मिले थे उनकी जमीनें ग्रामीण बैंक, कोऑपरेटिव बैंक और अन्य बैंकों के माध्यम से नीलाम हो रही थी। लोन एक लाख लिया था और वह अढाई या डेढ़ लाख रुपये बन गया। हमारी सरकार उन सभी गरीब किसानों को जो गांव में रहते हैं उनकी जमीन बचाने के लिए, वे मूलधन स्वयं देंगे और जो भी इंटरेस्ट होगा, उस समय के एक लाख रुपये के लोन पर, हम उसका 50 प्रतिशत या उससे अधिक उस किसान की जमीन बचाने के लिए खर्च करेंगे। इसके लिए 50 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। 50 करोड़ से अगर ज्यादा भी होगा तो उसका भी हम प्रबंध करेंगे।

40. वर्ष 2025-26 के दौरान एक लाख नये किसानों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाने का लक्ष्य रखा गया है। प्राकृतिक खेती करने वाले सभी किसानों को हिम परिवार रजिस्टर से जोड़ा जाएगा तथा साथ ही सर्टिफिकेशन के लिए नए किसानों को "Certified Evaluation Tool For Agriculture Resource Analysis" (CETARA Portal) पर रजिस्टर किया जाएगा।

41. मेरी सरकार ने राज्य में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का पर भारत में सबसे अधिक न्यूनतम समर्थन मूल्य प्रदान किया है। मैं वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गए मक्का के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य (मिनिमम सपोर्ट प्राइस) को 30 रुपये से बढ़कर 40 रुपये तथा गेहूं को 40 से बढ़ाकर 60 रुपये करने की घोषणा करता हूं। अभी गेहूं का सीजन शुरू हो रहा है।

इसके अतिरिक्त यदि कोई किसान 2 किलोमीटर से अधिक दूरी पर स्थित नोटिफाई कलेक्शन सेंटर पर स्वयं अपना मक्का और गेहूं बेचने के लिए आता है तो उसे 2 रुपये प्रति किलो हिसाब से Freight Subsidy दी जाएगी। किसानों को बेहतर मार्केटिंग के माध्यम से बेहतर मूल्य हेतु e-Commerce Platforms, NCDC (National Cooperative

Development Corporation) से भी जोड़ा जाएगा। अध्यक्ष महोदय जब एक किसान अपने घर में गोबर आधारित गेहूं की खेती करेगा तो उसे हम 60 रुपये प्रति किलो के हिसाब से क्रय करेंगे जबकि भारत सरकार यूरिया के द्वारा पैदा गेहूं के सिर्फ 24 रुपये किलो दे रही है। हमारे इस प्रयास से उसका ग्राफ बढ़ेगा और उसकी आजीविका , उसके जीवन जीने और काम करने की ओर ध्यान बढ़ेगा। वह अच्छी खेती करके अपने जीवन यापन को अच्छा बना सकता है। यह हिंदुस्तान में सबसे पहली ऐसी योजना है जिसके द्वारा गेहूं के मूल्य में 60 रुपये की वृद्धि हुई है।

42. विश्व में 78 प्रतिशत हल्दी उत्पदान के साथ भारत इसका सबसे बड़ा उत्पादक, उपभोक्ता और निर्यातक देश है। भारत में पैदा होने वाली हल्दी अपने High Curcumin Content के लिए प्रसिद्ध है। अतः प्रदेश के पास **प्राकृतिक हल्दी** के रूप में उत्पदान में आगे बढने का एक सुनहरा अवसर है। इस संदर्भ में मैं निम्न दो घोषणाएं करता हूं :-

- जिला हमीरपुर में स्पाइस पार्क का निर्माण किया जाएगा। इससे प्रदेश में उगाई जा रहे मसालों की वैल्यू एडिशन होगी व बाजार में एक नई पहचान मिलेगी।
- आगामी वित्त वर्ष में प्राकृतिक खेती के माध्यम से उगाए गई कच्ची हल्दी के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य को 90 रुपये प्रति किलोग्राम करने की घोषणा करता हूं।

43 एन0एस0 द्वारा ... शुरू

17-03-2025/1140/NS-HK/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

43. वर्ष 2025-26 के दौरान कृषि विभाग के सभी गवर्नमैंट फॉर्म्स जो भी सरकारी खेतों को प्राकृतिक खेती के अंतर्गत लाया जाएगा और किसानों को इन फॉर्म्स का और अधिक लाभ दिलाने के उद्देश्य से निम्न कदम उठाए जाएंगे। हमारा जो ग्रीन हिमाचल का जो उद्देश्य है, उसमें हिमाचल प्रदेश हिंदुस्तान में अभी तक सभी देशों में नंबर वन पर है और उसको हम और तेजी से नंबर वन स्थान पर ले जाने की कोशिश कर रहे हैं और जितने भी हमारे एग्रीकल्चर के फॉर्म्स हैं उसमें हम नेचुरल खेती के बीज उगाएंगे।

- 15 से 20 प्रतिशत हिस्से में पारंपरिक फसलों (हल्दी, अदरक, अरबी, कटहल,रतालू आदि) की खेती की जाएगी और विभिन्न प्रकार की फसलों हेतु पांच नए मॉडल फार्म विकसित किए जाएंगे।
- आई0सी0ए0आर0 और सी0पी0आई0आर0 द्वारा विकसित एस0ओ0पी0 के तहत खरीफ वर्ष 2025 के आलू के बीज का उत्पादन 8 पोटैटो डवलपमैंट स्टेशन्ज में फिर से शुरू किया जाएगा।

44. प्रदेश की कृषि क्षेत्र में वर्षा से आलू एक महत्वपूर्ण फसल है। राज्य में कुल सब्जी उत्पादन में आलू का 20 प्रतिशत हिस्सा है। अतः आलू की फसल को बढ़ावा देने के लिए हमारी सरकार ऊना जिले में लगभग 20 करोड़ रुपये की लागत से 500 KG Per Hour की क्षमता वाले पोटैटो प्रोसैसिंग प्लांट को स्थापित करने जा रही हैऍ जोकि प्रदेश में वर्ष के दौरान 3400 हैक्टेयर से उगने वाले आलू की दोनों मौसमों की फसलों के लगभग 54,200 मीट्रिक टन आलू उत्पादन करने वाले किसानों को सहायता प्रदान करने में सहायक होगा। ऊना में आलू बहुत होता है, जब से स्वां चैनलाइजेशन हुआ है। ऊना के क्षेत्र में आलू बहुत होता है पर जब मार्केट में जाता है तो किसान को बहुत कम पैसा मिलता है। इसलिए उसका प्रोसैसिंग यूनिट वहीं लगाकर उसको हम आगे बढ़ाने की दिशा में, ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में और किसान की जेब में पैसा आए, उस दिशा में हमारी सरकार आगे बढ़ रही है।

17-03-2025/1140/NS-HK/2

45. गेहूं और मक्का के बेहतर भंडारण के लिए प्रदेश में उच्च तकनीक से चालित Silos स्थापित किए जाएंगे।

46. अध्यक्ष महोदय, सरकार प्रदेश के किसानों के उत्थान के लिए प्रतिबद्ध है और "**हिमाचल प्रदेश फसल विविधीकरण संवर्धन परियोजना**" इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण प्रयास है। आगामी वित्त वर्ष में सरकार इस परियोजना हेतु 154 करोड़ रुपये का व्यय करेगी। परियोजना के तहत निम्न महत्वपूर्ण कार्य किए जाएंगेः-

- 100 गांव में सिंचाई योजना का निर्माण करके उन्हें लोकल कमेटीज को ट्रांसफर किया जाएगा।
- कृषि यंत्रीकरण पर सहायता प्रदान करने के लिए लगभग 10 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।
- परियोजना क्षेत्र के लाभार्थी किसानों के लिए 1500 प्रशिक्षण शिविर आयोजित किए जाएंगे। लगभग 4000 Demonstrations of Vegetable Cultivation आयोजित की जाएंगी।
- मिलेट्स के प्रचार-प्रसार के साथ खाद्यान्न उत्पादकता पर लगभग 2400 डेमोंसट्रेशन्स आयोजित की जाएंगी।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

17.03.2025/1145/RKS/HK-1

➤"**मुख्य मन्त्री खेत संरक्षण योजना**" को आगे बढ़ाते हुए अब किसानों को जंगली जानवरों से फसलों की रक्षा हेतु Solar Fencing जाली दार और कान्टेदार बाड़बंदी में सहायता प्रदान की जाएगी।

बागवानी

47. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश में बागवानी न केवल किसानों/बागवानों के लिए आजीविका का स्रोत है बल्कि यह ग्रामीण विकास, रोजगार सृजन और आर्थिक स्थिरता का प्रमुख स्तम्भ है। हमारी सरकार ने बागवानों की समस्याओं को समझते हुए Universal Carton का इस्तेमाल आरम्भ किया और MIS के अंतर्गत लगभग 153 करोड़ रुपये की देनदारी चुकाई। मैं वर्ष 2025-2026 के लिए इस क्षेत्र में निम्न घोषणाएं करता हूँ :-

> 4 हज़ार हैक्टेयर में 257 क्लस्टरों के लिए Topographic Survey किया जाएगा।

> प्रदेश में किसान उद्यम नवाचार केन्द्र स्थापित किया जाएगा जोकि बागवानी उत्पाद की Marketing, Processing, आदि में सहायक होगा।

114 Lift Irrigation Schemes वित्तीय वर्ष के अन्त तक पूरी की जाएगी।

➤ HP SHIVA परियोजना के तहत वर्ष 2025-2026 में 100 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

48. पूर्व की सरकारों ने बागवानी के क्षेत्र में डिजिटल प्रौद्यौगिकी को महत्व नहीं दिया, जिसके कारण इस क्षेत्र में डिजिटल कान्ति नही आ सकी। अतः वर्तमान सरकार द्वारा बागवानी क्षेत्र को मजबूत करने के लिए 5 करोड़ रूपये के प्रावधान के साथ डिजिटल एग्रीटेक सेवाएं सृजित की जाएगी। जिसमें बागवानी प्रथाओं को बढ़ावा देने, उत्पादकता में सुधार, विपणन के लिए डिजिटल प्लैट फार्म और कृषि आय को बढ़ाने के लिए प्रौद्यौगिकी और डिजिटल उपकरणों का प्रयोग किया जाएगा।

49. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Weather Based Crop Insurance Scheme के अन्तर्गत 60 हजार से अधिक बागवानों को लाभान्वित करने के साथ-साथ उन्हें आर्थिक सुरक्षा प्रदान की जा रही है। इस योजना में अब तीन और फसलों लीची, अनार तथा अमरूद को भी शामिल किया गया है। अब इस योजना के अन्तर्गत सेब के लिए 36, आम के लिए 56, प्लम के 29, आडू के लिए 16. नीम्बू के लिए 58, आनार के लिए 21, लीची के लिए 38 और अमरूद के लिए 22 ब्लॉकों को लाया जाएगा। यह कदम कृषि क्षेत्र विकास में एक महत्वपूर्ण योगदान देगा और साथ ही यह किसानों की भलाई के लिए सरकार की प्रतिबद्धता को दर्शाता है।

50. राज्य में Sub tropical बागवानी को बढ़ावा देने के लिए Sub Tropical फलों को High Density Plantation के अन्तर्गत लाया जाएगा। इसके साथ ही 48 सिंचाई योजनाओं का कार्यान्वयन किया जाएगा जिससे लगभग 5 हजार किसान परिवार लाभान्वित होंगे। इसके लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

मत्स्य पालन

51. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में लगभग 20 हजार से अधिक मछुआरे, मत्स्य कृषक तथा अन्य कारोबारी मछली पालन व्यवसाय से अपनी आजीविका कमा रहे हैं। इस क्षेत्र में कार्यरत भाईयों व बहनों की आय में वृद्धि के उद्देश्य से मैं निम्न घोषणाएं करता हूंः-

> वर्तमान में प्रदेश सरकार जलाशयों से मछली प्राप्त कर रहे मछुआरों और मत्स्य कृषकों से 15 प्रतिशत दर से Royalty लेती है। मैं इस Royalty की दर को घटाकर 7.5 प्रतिशत करने की घोषणा करता हूँ। इससे इन्हें लगभग 75 लाख रुपये का लाभ होगा।

> ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के उद्देश्य से मुख्य मन्त्री मत्स्य पालन योजना के तहत निजी क्षेत्र में 80 प्रतिशत सब्सिडी के साथ 20 हैक्टेयर नए मछली के तालाबों का निर्माण किया जाएगा।

> 120 नई ट्राऊट इकाइयों का निर्माण किया जाएगा।

> पतलीकूहल में एक ट्राऊट फिश ब्रूड बैंक स्थापित किया जाएगा।

>राज्य के मछुआरों को Fish Transportation हेतु तिपहिया वाहन व मोटर साईकल वितरित किए जाएंगे।

> मछुआरों की पुरानी नाव बदलकर नई नाव खरीदने के लिए पात्रता के अनुरूप 40 से 60 प्रतिशत का अनुदान दिया जाएगा।

52. इसके अतिरिक्त 10 Biofloc Culture Units, 3 Trout Hatcheries, 4 Fish Feed Mills, 2 Ice Plants, 5 Biofloc Fish Ponds और 2 Ornamental Fish Farming Units का निर्माण किया जाएगा।

श्री बी0एस0द्वारा... जारी

17.03.2025/1150/बी.एस./वाई.के./-1

मुख्य मंत्री जारी...

वन विभाग

53. अध्यक्ष महोदय, ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास व ग्रीन हिमाचल के सपने को साकार करने के उद्देश्य से वन क्षेत्र के विस्तारीकरण के विभिन्न कार्यक्रम को नया रूप दिया गया है। वर्ष 2025-26 के लिए 5,000 हैक्टेयर का वृक्षारोपण लक्ष्य तय किया गया है जिसमें जंगली फलों के पौधों और अन्य फलदार पेड़ों के पौधों को प्राथमिकता दी जाएगी। हमारी सरकार ने यह पहल की इससे न सिर्फ वन क्षेत्र में जैव विविधता आएगी बल्कि बंदर वह अन्य जीवों को आबादी में आने से रोका जाएगा।

54 वन प्रबंधन तथा वन क्षेत्र विस्तार में समुदायों की भागीदारी को बढ़ाना देने हेतु मैं राजीव गांधी वन संवर्धन योजना लागू करने की घोषणा करता हूं। इस योजना में युवक मंडल, महिला मंडल तथा स्वयं सहायता समूह को बंजर भूमि पर फलदार वृक्ष एवं अन्य उपयोगी पौधों के वृक्षारोपण और उनकी सुरक्षा के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इन्हें एक हेक्टर से 5 हेक्टेयर तक के पौधारोपण क्षेत्र प्रबंधन के लिए दिए जाएंगे। औसत रोपण क्षेत्र दो हेक्टर से अधिक होने का अनुमान है। 2 हैक्टेयर क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए पहले वर्ष में इन समूहों को महिला मंडल युवक मंडल स्वयं सहायता समूहों को पौधे लगाने के लिए 2,40,000 रुपये फलदार और अन्य वृक्षों को लगाने व संबंधित कार्य करने के लिए वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान किए जाएंगे। यानी की जो प्लांटेशन होगा वह महिला मंडल और युवक मंडल के द्वारा होगा। उसमें एक लाख रुपये महिला मंडल को बाढ़ को लगाने के लिए दिए जाएंगे और महिला मंडल और युवक मंडल जो वन विभाग द्वारा प्लांटेशन की जाती है, वन विभाग द्वारा प्लांटेशन न करने के बाद उसको महिला मंडल व युवक मंडलों के द्वारा दिया जाएगा। उन्हें पहले साल पौधा लगाने के लिए और बाड़ लगाने के लिए 2,40,000 रुपये दिए जाएंगे। नेता प्रतिपक्ष द्वारा लगाया गया पौधा भी ऑक ओवर में लगा है और वह सूख रहा था। मैंने पूछा कि यह पौधा किसने लगाया है? तब मुझे बताया गया कि आदरणीय जय राम ठाकुर जी ने लगाया है। जब वह सूख रहा था तो मैंने उसमें अपने कार्यकाल में खाद डाली और उसमें अब थोड़े फूल निकलने लग गए हैं। क्योंकि जब मैं

आया तो वह सूख रहा था। मेरे कहने का मतलब है कि हम प्लांटेशन को भी हरा करने में लगे हुए हैं। अध्यक्ष महोदय, यह एक ऐसी योजना है जिसमें गांव में बैठा

17.03.2025/1150/बी.एस./वाई.के./-2

हुआ व्यक्ति अपने घर के पास खाली वन भूमि देखेगा और पौधा लगाएगा। इसके अलावा उनके लिए और क्या आ रहा है? इसे बाद अलगे वर्ष 5 साल तक सर्वाइवल प्रतिशत अगर वह 100 पौधे लगता है और 50 प्रतिशत तक उसका सर्वाइवल होता है, इसके बाद भी सर्वाइवल प्रतिशत 50 प्रतिशत या इससे अधिक होने पर दूसरे, तीसरे, चौथे और पांच वर्ष तक सालाना 1,00,000 रुपये मिलता रहेगा तथा 50 प्रतिशत से कम होने पर प्रोत्साहन तथा संरक्षण राशि दी जाएगी। इस प्रकार एक महिला मंडल जब वह पहले पौधा लगाएगा फिर उसकी देखभाल अगले साल करेगा। उन 100 पौधों में से 50 सरवाइव कर गए तो उसे 1,00,000 रुपये मिल जाएगा और उसके बाद एक और अगर फिर 50 सरवाइव कर गए, जंगली पशु रहते हैं, बंदर रहते हैं तो वे पौधों को उजाड़ देते हैं तो फिर उसको 1,00,000 रुपया और मिलेगा। जब तीसरे साल पौधा जड़ पकड़ लेगा और बड़ा हो जाएगा,फिर उसकी देखभाल ही करनी है तो 1,00,000 रुपया और मिलेगा। जब वह पौधा बड़ा हो जाएगा और फल देने वाला जो जाएगा तो उसे 1 लाख रुपये देकर वह जगह वन विभाग को चली जाएगी। इस प्रकार कुल 6,40,000 रुपये की राशि प्रत्येक समूह को मिल सकेगी। कई बार क्या होता है कि फॉरेस्ट वाले कहते हैं कि यह फॉरेस्ट भूमि है और उसमें बाढ़ लगानी होगी तो 1,00,000 रुपये फॉरेस्ट वाले भी बाढ़ लगाकर महिला मंडलों व युवक मंडलों को दे सकते हैं। पांच साल में 6,40,000 रुपये घर में बैठकर महिला मंडल के लोग अपना और युवक मंडल के लोग स्वयं सहायता समूहों को मिलेगा। इससे निश्चित तौर पर ग्रामीण अर्थव्यवस्था में सुधार होगा। इन सभी वन क्षेत्र में जियो टैग किया जाएगा और ऑनलाइन मॉनिटरिंग की जाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपया ब्यय किया जाना प्रस्तावित है।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.05.2025/1155/DT/YK/1

55. Corporate Social Responsibility (CSR) के अंतर्गत एक नई Adoption योजना लाई जा रही है। जिसमें बंजर भूमि पर वृक्ष लगाए जाएंगे। इस प्रयास से न केवल प्रदेश के वनों में वृद्धि होगी, बल्कि स्थनीय समुदायों को आजीविका भी सुनिश्चित होगी। हमारे पास बड़े-बड़े बैंक के अधिकारी व बड़े-बड़े उद्योगपति आते हैं इसके अतिरिक्त हमें CSIR के तहत फंड आता है। हमने उनसे कहा कि आप एक पहाड़ी चुनिए और उस पहाड़ी में पांच साल तक आप पौधे लगाईए और जब उन पहाड़ियों में जंगल बन जाएंगे तो उन पहाड़ियों को हमें वापिस दीजिए। इस योजना के तहत अगर कोई एम्बुलेंस दान करता है तो उनको भी गाईड किया जाएगा ।

56. World Bank, KFW और JICA की सहायता से चल रही तीन परियोजनाओं के तहत अगले वर्ष के दौरान लगभग 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाने प्रस्तावित है।

57. हिमाचल प्रदेश आक्रामक प्रजातियों जैसे Lantana और Parthenium Grass के प्रसार, चीड़ की सूखी सुईयों और कृषि-अवशेषों से होने वाली जंगल की आग, जैव विविधता की हानि, जल संकट, आवास और पारंपरिक आजीविका के नुकसान, जलवायु परिवर्तन और आपदा जोखिम जैसी गंभीर चुनौतियों का सामना कर रहा है। भूस्खलन जैसी आपदाएँ स्थानीय समुदायों की आजीविका को अस्थिर कर रही हैं। मेरी सरकार इन समस्याओं को अवसर में बदलने के लिए कचरे को Biochar, Bio-Energy, Bio-Fertilizers, Bio-Pesticides, Green Energy और Carbon Credits जैसे उत्पादों में परिवर्तित करने का प्रस्ताव रखती है, जिससे न केवल कार्बन उत्सर्जन कम होगा, बल्कि ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और टिकाऊ आजीविका सुनिश्चित होगी।

58. हिमाचल प्रदेश अपनी प्राकृतिक सुन्दरता, घने वन, बर्फ से ढके पहाड़, जैव विविधता और समृद्ध सांस्कृतिक विरासत के कारण Eco-Tourism के लिए एक आदर्श स्थल है। Eco-Tourism स्थानीय समुदायों की आर्थिक स्थिति को सुधारने में भी महत्वपूर्ण योगदान

देता है। इस से लोगों को रोज़गार के नए अवसर मिल रहे हैं। इस दिशा में हमारी सरकार निम्न कदम उठा रही हैः-

17.05.2025/1155/DT/YK/2

- सरकार ने वर्ष 2024 में Eco-Tourism नीति को संशोधित किया है। इस नीति से Eco-Tourism गतिविधियों को गति मिलेगी।
- वर्ष 2024 में 7 Eco-Tourism साइटों के लिए संचालकों (Operators) को चयनित किया गया है। अगले चरण में 78 नई Eco-Tourism साईटों को आबंटित किया जाएगा।
- वन विभाग के विभिन्न सर्कल में Eco-Tourism Societies गठित की गई हैं जो इन गतिविधियों को नियन्त्रित एवं संचालित करेगी।
- विभिन्न Eco-Tourism गतिविधियों के माध्यम से अगले 5 वर्षों में लगभग 200 करोड़ रूपये का अतिरिक्त राजस्व अर्जित किया जाएगा।

59. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में Forest Clearance के मामलों को अभूतपूर्व तेजी से Process किया है। पिछले दो वर्षों में 208 मामलों में FCA के तहत मंजूरी प्रदान की गई है। इस पहल से वर्षों से रुके हुए Projects को शुरू किया जा सका है। इसी तरह से Forest Rights Act के तहत भी 560 मामलों में स्वीकृति प्रदान की गई है। यह मेरी सरकार द्वारा किए जा रहे व्यवस्था परिवर्तन का ही परिणाम है।

पर्यटन एवं नागरकि उड्डयन

60. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश एक खूबसूरत गन्तव्य ही नही अपितु देव भूमि भी है। यहां पर्यटन की अपार सम्भावनाएं है। धार्मिक पर्यटन, Adventure Tourism तथा Health Tourism प्रदेश में पर्यटन विकास के मुख्य स्तम्भ है। इस दिशा में हमारी सरकार पर्यटन को बढ़ावा देने हेतु कई महत्वपूर्ण निर्णय लेने जा रही है।

पैरा संख्या-61 एन0जी0 द्वारा जारी....

17.03.2025/1200/ए.जी.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री...........जारी

पैरा संख्या-60 के पश्चात.......जारी

61. अध्यक्ष महोदय, इस प्रदेश के सभी क्षेत्रों तथा विशेषकर कांगड़ा जिले को अन्तर्राष्ट्रीय Tourist Map पर लाने के लिए पूर्व में घोषित प्रयासों का तेजी से कार्यान्वयन किया जा रहा है। कांगड़ा में गगल स्थित हवाई अड्डे के विस्तारीकरण के लिए भू-अधिग्रहण का कार्य आरम्भ कर दिया गया है तथा इसे निर्धारित समय अवधि में पूरा कर लिया जाएगा। भू-अधिग्रहण के पूरा होते ही इसके निर्माण कार्य को भी शुरू कर दिया जाएगा। 2025-2026 के दौरान इसके लिए लगभग 3 हज़ार करोड़ रुपये व्यय करने का प्रस्ताव है। मण्डी के बल्ह में प्रस्तावित Airport के सम्बन्ध आगामी कार्रवाई हेतु मामला Airport Authority of India के साथ उठाया जाएगा।

62. अध्यक्ष महोदय, मुझे इस सदन को सूचित करते हुए हर्ष हो रहा है कि मेरी सरकार New Tourism Destinations को दो चरणों में लगभग 2 हज़ार 400 करोड़ रुपये की लागत से विकसित करेगी। प्रथम चरण में 2025-2026 में निम्न कार्य किए जाएंगे :-

- मनाली, कुल्लू, नग्गर व नादौन में वैलनेस सेन्टर।
- धर्मशाला, शिमला व मण्डी में आईस स्केटिंग रिंकस।
- पालमपुर और नगरोटा बगवां का सौन्दर्यकरण।
- बाबा बालकनाथ मन्दिर परिसर में सुविधाएं पर्यटन।
- Adventure Tourism को बढ़ावा देने के लिए नादौन में रॉफ्टिंग सेन्टर व प्रदेश के जलाशयों में Water Sports एवं अन्य Adventure Sports की शुरुआत।

17.03.2025/1200/ए.जी.-एन.जी./2

63. पर्यटकों को हिमाचल में आकर्षित करने के लिए Home Stay Units की एक महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यह Units न केवल महंगे होटलों का एक विकल्प हैं बल्कि यह ग्रामीण क्षेत्रों में पर्यटकों को अधिक समय के लिए रुकने के लिए भी प्रेरित करते हैं। मैं प्रदेश के युवाओं को रोजगार देने के लिए तथा ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए एक नई योजना "**मुख्यमन्त्री पर्यटन स्टार्ट अप योजना**" शुरू करने की घोषणा करता हूं। इसके अन्तर्गत प्रदेश के गैर जनजातीय क्षेत्रों में हिमाचली युवाओं द्वारा Home Stay Units और Hotel बनाने के लिए ऋण पर 4 प्रतिशत Interest Subvention तथा जनजातीय क्षेत्रों में 5 प्रतिशत Interest Subvention दी जाएगी।

अध्यक्ष महोदय, यदि कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपये का लोन लेता है और 9 प्रतिशत के ब्याज दर पर लेता है, जनजातीय क्षेत्र जैसे पांगी, किन्नौर, रिकांगपिओ, पूह, स्पिति, लाहौल, कुपवी आदि क्षेत्रों में यदि कोई व्यक्ति 2 करोड़ रुपये का होटल बनाता है और उस पर यदि बैंक द्वारा 9 प्रतिशत का ब्याज लिया जाता है तो उसमें से 5 प्रतिशत ब्याज सरकार द्वारा वहन किया जाएगा। इन क्षेत्रों के अलावा अन्य क्षेत्रों में सरकार द्वारा 4 प्रतिशत ब्याज वहन किया जाएगा। इसके साथ ही राष्ट्रीय राज मार्गों तथा जिला मुख्यालयों पर चलाने के लिए प्रदेश के युवाओं को 30 प्रतिशत उपदान पर Food Vans उपलब्ध करवाई जाएंगी। योजना के तहत 50 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे।

अध्यक्ष महोदय, आज कल फूड वैन्ज़ का कंसेप्ट चला हुआ है। कीरतपुर-मनाली रोड, शिमला से कुफरी रोड और अन्य रोड्स पर बहुत अधिक संख्या में पर्यटक आते हैं। प्रदेश का कोई भी युवा यदि 10 लाख रुपये की फूड वैन खरीदेगा तो 3 लाख रुपये और यदि एक करोड़ रुपये की फूड वैन खरीदेगा तो 30 लाख रुपये का उपदान उपलब्ध करवाएंगे।

17.03.2025/1200/ए.जी.-एन.जी./3

64. हिमाचल प्रदेश में पर्यटन के क्षेत्र में अब ग्रामीण क्षेत्रों में विकास होगा क्योंकि अधिकांश शहरी क्षेत्रों में पर्यटन का ढांचागत विकास लगभग अपनी सीमा के अनुसार हो चुका है। हम एक नई योजना के तहत प्रदेश में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 200 3-Star, 4-Star, 5-Star या उससे ऊपर 7-Star तक के होटल स्थापित करने के लिए निजी क्षेत्र को निवेश के लिए आमन्त्रित करेंगे। इन Projects में High End Health and Wellness Centres, Senior Citizen Townships, High Value Tourism Experience Centres और विश्वस्तरीय सुविधा युक्त Tourist Attraction स्थापित करने को प्राथमिकता दी जाएगी। इस Projects, Hotels और Resorts को स्थापित करने के लिए Complete Application Submit करने पर एक महीने में सारी Permissions दे दी जाएंगी।

पैरा संख्या - 65.......श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

17.03.2025/1205/ ए0जी0-पी0बी0 /-1

65. प्रदेश में धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए प्रथम चरण में माता श्री चिन्तपूर्णी मंदिर के सौन्दर्यीकरण के लिए 58 करोड़ रुपये की Detailed Project Report स्वीकृत होते ही इसका काम शुरू कर दिया जाएगा। इसी प्रकार माता श्री ज्वालाजी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपये, माता श्री नैना देवी मंदिर के लिए 100 करोड़ रुपये तथा धर्मशाला के तपोवन में अन्तर्राष्ट्रीय Convention Centre के निर्माण के लिए 200 करोड़ रुपये व्यय किए जाएंगे। दूसरे चरण में माता श्री ब्रजेश्वरी मंदिर कांगड़ा, चौरासी मंदिर भरमौर, श्री त्रिलोकीनाथ मंदिर लाहौल को सम्मिलित किया जाएगा।

66. मण्डी जो कि छोटी काशी के नाम से प्रसिद्ध है, वहां शिवधाम की परियोजना को प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण करके जनता को समर्पित किया जाएगा। इसके लिए आगमी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार द्वारा 100 करोड़ रुपये के व्यय का अनुमान लगाया गया है।

67. महोदय, कांगड़ा जिले को **Tourism Destination** बनाने के लिए मेरी सरकार के लक्ष्य की दिशा में पौंग डैम के साथ-साथ निकटम क्षेत्रों के विकास हेतु नगरोटा सूरियां, खब्बल

व Wellness Centre देहरा की डी0पी0आर0 बना कर भारत सरकार के पर्यटन मंत्रालय को भेज दी गई है। इसके अतिरिक्त प्रदेश के Challenge Based Destination Development हेतु काज़ा ओर रक्छम व छितगुल को पर्यटन गंतव्यों के रूप में विकसित किया जाएगा। चांशल को भी पर्यटन स्थल के रूप में डेवल्प किया जाएगा।

68. माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि आपको मालूम है हमारी सरकार द्वारा वनखंडी, कांगड़ा में **Zoological Park** का निर्माण किया जा रहा है और अब हम इसके साथ एक अत्याधुनिक "**Planetarium**" स्थापित करने जा रहे हैं। यह न केवल स्थानीय निवासियों को स्वःरोजगार प्रदान करेगा और पर्यटकों को आकर्षित करेगा, बल्कि खगोल विज्ञान और अंतरिक्ष विज्ञान में रुचि और जागरूकता भी बढ़ाएगा। इसके अलावा, यह बच्चों के लिए प्रमुख आकर्षण और शैक्षिणक विकास का केन्द्र बनेगा। साथ ही वनखंडी के क्षेत्र को एक प्रमुख पर्यटक स्थल के रूप में विकसित करने में सहायक होगा।

69. सरकार स्वास्थ्य पर्यटन को बढ़ावा देने के लक्ष्य से प्रदेश में चार नए फाइव स्टार स्तर के "**Natural care Wellness Centre**"खोलेगी। ये केन्द्र शांत प्राकृतिक वातावरण में योग, ध्यान, हर्ब्ल उपचार और पारंपरिक चिकित्सा का अनूठा अनुभव प्रदान करेंगे। साथ ही यहां दिया जाने वाला भोजन व अन्य खाद्य सामग्री भी विशुद्ध रूप से प्रकृतिक होगी। इस पहल का उद्देश्य प्रदेश को एक प्रमुख स्वास्थ्य पर्यटन स्थल के रूप में स्थापित करना और पर्यावरण-अनुकूल प्रथाओं को बढ़ावा देना होगा।

70. सरकार द्वारा रक्कड़, पालमपुर, सुलतानपुर,जसकोट और शारबो (किन्नौर) में हैलीपोर्टस का निर्माण और संचालन वर्ष 225-26 के भीतर कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त आलू ग्राउंड मनाली, धारकियारी (नाहन), बिलासपुर, बसाल (सोलन) और जनकौर हार (ऊना) के लिए वर्ष 2025-26 के दौरान Obstacle Limited Surfaces Survey, डी0पी0आर0 जैसी औपचारिकताएं पूर्ण कर ली जाएंगी और इनमें जैसे ही औपचारिकताएं पूर्ण होती है इनके निर्माण की प्रक्रिया भी शुरू कर दी जाएगी।

71. अध्यक्ष महोदय, अन्तर्राष्ट्रीय ख्याती प्राप्त कांगड़ा चाय को GI Tag मिला हुआ है, जोकि प्रदेश के लिए एक गौरव का विषय है। Tea-Tourism प्रदेश की आर्थिकी में बहुत बड़ी भूमिका निभा सकता है। इस क्षेत्र में रोजगार की बहुत बड़ी संभावनाएं है। हम वर्तमान कानून में संशोधन करके Tea-Tourism को बढ़ावा देने के लिए चाय के बागानों को सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल की तर्ज पर Eco-Tourism Destination के रूप में विकसित करेंगे और निवेशकों को बिना किसी समस्या के सभी अनुमतियां प्रदान करेंगे। इससे न केवल Tea-Plantation को बढ़ाया और बचाया जा सकेगा बल्कि हिमाचल की चाय को विश्व स्तर पर पहचान मिलेगी।

श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

17.03.2025/1210/एपी/एएस/01

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज

72. अध्यक्ष महोदय, राज्य सरकार ग्रामीण अर्थव्यवस्था के विकास एवं पंचायती राज को सुदृढ़ बनाने के लिए प्रतिबद्ध है। व्यवस्था परिवर्तन की ओर आगे बढ़ते एवं ग्रामीण अर्थव्यवस्था आजीविका में सुधार लाने एवं आत्मनिर्भर स्वच्छ और समृद्ध हिमाचल के संकल्प को साकार करने की दिशा में मजबूत कदम उठा रहे हैं। इस प्रयास को जारी रखते हुए, 2025-26 के दौरान मैं निम्न कार्यों की घोषणा करता हूं:-

राज्य में प्रशासनिक व्यवस्था को और अधिक प्रभावी एवं सुचारु बनाने के लिए हम ब्लॉकों का पुनर्गठन करेंगे। यह कदम संसाधनों के बेहतर उपयोग, प्रशासन में कार्यकुशलता लाने और सरकारी सेवाओं को आसानी से आम जनता तक पहुंचाने में कामगार होगा।

हमारे ग्रामीण संस्थानों को सशक्त बनाने के लिए कैपेसिटी बिल्डिंग अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस दृष्टि से राज्य ग्रामीण विकास संस्थान एस0आई0आर0डी0 के अंतर्गत 09 विस्तार प्रशिक्षण केंद्र एक्सटेंशन ट्रेनिंग सेंटर स्थापित किये जाएंगे। ये केंद्र पंचायत प्रतिनिधियों, ग्रामीण विकास कार्यकर्ताओं, अधिकारियों व कर्मचारियों को उच्च स्तरीय

प्रशिक्षण प्रदान करेंगे जिससे वे और अधिक प्रभावी ढंग से लोगों की सेवा करने में सक्षम होगे।

स्थानीय कारीगरों और उद्यमियों को बढ़ावा देने के लिए नये स्तर पर हिम ईरा शॉपस, हिमाचली हाट साथ ही Wayside Amenities का निर्माण आरंभ किया जाएगा। इससे पारंपरिक हस्त शिल्प, हथकरघा और कृषि उत्पादों को स्थायी मंच मिलेगा जिससे रोज़गार के नये अवसर सृजित होंगे और ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। विशेष रूप से Wayside Amenities स्कीम के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह को प्रोत्साहित किया जाएगा ताकि उन्हें और अवसर मिले। प्रथम चरण में योजना राज्य राजमार्गों, राष्ट्रीय राजमार्गों और एक्सप्रैसवे के किनारे लागू की जाएगी। इसके तहत विश्राम स्थलों, फूड कोर्ट, स्वयं सहायता समूह के उत्पाद के लिए रिटेल आउटलेट्स और यात्रियों के लिए आवश्यक सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इससे ग्रामीण उद्यमिता को बढ़ावा मिलेगा और सड़क सुरक्षा में भी सुधार होगा। जिससे यात्रियों को सुरक्षित विश्राम स्थल मिलेंगे। यह दूरदर्शी योजना स्थानीय समुदायों और यात्रियों दोनों के लिए लाभदायक होगी।

17.03.2025/1210/एपी/एएस/02

स्वयं सहायता समूह (SHG) को आत्मनिर्भर बनाने के लिए मोबाइल फूड वैन दी जाएंगी। जो न केवल भोजन उपलब्ध करवाएंगी, बल्कि समूहों द्वारा तैयार किये गए उत्पादों की बिक्री का भी माध्यम बनेगी।

पंचायती राज संस्थओं को वित्तीय रूप से मजबूत बनाना हमारी प्राथमिकता है। इसके लिए इन संस्थानों को उनकी संपत्तियों के बेहतर लीज़ मैनेजमेंट के माध्यम से आय बढ़ाने के विशेष प्रयास करेंगे। पानी की योजनाओं का प्रबंधन पंचायत स्तर पर देंगे ताकि वह अपनी आय में बढ़ोतरी कर सके। इससे सरकारी अनुदानों पर उनकी निर्भरता में कमी आएगी और ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

वन विभाग के सहयोग से मनरेगा के तहत वृक्षारोपण गतिविधियों के लिए एक स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर लागू किया जाएगा जिससे पौधारोपण योजनाओं को प्रभावी

और सुनियोजित बनाया जाएगा। यह पहल न केवल प्रदेश के ग्रीन कवर को बढ़ाएगी बल्कि पशुधन के लिए चारे की स्थाई व्यवस्था भी सुनिश्चित करेगी।

(उपाध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

73. मैंने पिछले वर्ष के बजट में मनरेगा मजदूरों की मजदूरी 60 रुपये बढ़ाई थीं जोकि अप्रत्याशित थी और समतुल्य राज्यों में सबसे अधिक कही जा सकती है। मैं घोषणा करता हूं कि मनरेगा मज़दूरों के उत्थान के लिए एवं उन्हें उचित सुविधा देने के लिए एक व्यापक योजना अगले वित्त वर्ष में लागू की जाएगी। इसके अलावा मैं मनरेगा मज़दूरों को 20 रुपये दिहाड़ी बढ़ाकर 320 रुपये करने की घोषणा करता हूं।

74. नेशनल रूरल लाइवलीहुड मिशन के अंतर्गत 2025-26 में 4000 योग्य अभ्यर्थियों को कौशल प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। इनमें से 70 प्रतिशत को सुनिश्चित रोज़गार भी उपलब्ध करवाया जाएगा।

75. वर्ष 2025-26 हेतु 15वें वित्त आयोग के तहत पंचायतों में विकास हेतु 452 करोड़ रुपये तथा राज्य वित्तायोग के तहत 467 करोड़ व्यय किये जाएंगे।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी---

17.03.2025/1215/AT/ऐ0एस0/1

(अध्यक्ष महोदय पदासीन हुए)

76. मैं, पंचायती राज संस्थाओं के प्रतिनिधियों का मानदेय बढ़ाने की सहर्ष निम्न घोषणाएं करता हूँः-

अध्यक्ष, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, जिला परिषद को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 19,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सदस्य, जिला परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,300 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

अध्यक्ष, पंचायत समिति को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 12,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, पंचायत समिति को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सदस्य, पंचायत समिति को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रधान, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-प्रधान, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 5,100 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

सदस्य, ग्राम पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 1050 रुपये प्रति ग्राम पंचायत बैठक हेतु मानदेय मिलेगा।

17.03.2025/1215/AT/ऐ0एस0/2

श्रम एवं रोज़गार

77. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा युवाओं को रोजगार के अवसर प्रदान करने हेतु श्रम एवं रोज़गार विभाग के माध्यम से वर्ष 2025-2026 के लिए 50 Campus Interviews को आयोजित करने का लक्ष्य रखा है। इसके अतिरिक्त सरकार द्वारा राजीव गांधी स्वरोजगार स्टार्ट-अप योजना के तहत पात्र आवेदकों को ई-टैक्सी खरीदने हेतु 2 करोड़ 91 लाख रूपये की सब्सिडी प्रदान की गई है। सरकार वित्त वर्ष 2025-2026 में भी विभिन्न सरकारी विभागों एवं निकायों से प्राप्त ई-टैक्सी की मांग अनुसार पात्र आवेदकों को इस योजना के अन्तर्गत सब्सिडी प्रदान करना जारी रखेगी। इस योजना को और विकसित

करते हुए तथा Natural and Green Himachal के लक्ष्य को ध्यान में रखते हुए मै निम्न घोषणाएं करता हूं :-

तीन हजार डीजल पैटोल वाले Taxi वाहनों को इलैक्ट्रिक Taxi (e-Vehicles) में चरणबद्ध तरीके से परिवर्तित किया जाएगा। सरकार प्रदेश के Taxi तथा ऑटो रिक्शा मालिकों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से इन वाहनों को e-Vehicles/e-rickshaw में परिवर्तित करने के लिए 40 प्रतिशत तक की Subsidy देगी ।

सरकार राज्य के बेरोज़गार युवाओं को रोजगार उपलब्ध करवाने के लिए एक हजार बस रूटों के नए परमिट निजी क्षेत्र को आवंटित करेगी। सरकार इन रूटों हेतु बस अथवा टैम्पों ट्रैवलर की खरीद पर e-Vehicles के लिए 40 प्रतिशत व डीजल/पैट्रोल से चलने वाले वाहनों की खरीद पर 30 प्रतिशत तक की Subsidy / Viability Gap Funding देगी। इसके के लिए 66 करोड़ रूपये के बजट का प्रावधान किया गया है। अध्यक्ष महोदय, 3 हजार ई-टैक्सी वाले जो पुराने हैं, अगर वे नई ई-टैक्सी खरीदना चाहते हैं, ई-रिक्शा खरीदना चाहते हैं, ई-ऑटो चलाना चाहते हैं तो उनको 40 प्रतिशत की सब्सिडी मिलेगी। एक हजार बस रूटों के नए परमिट मिलेंगे । एक हजार जो नए बस रूट होंगे, जो इलैक्ट्रिकल बस खरीदेगा, उसे 40 प्रतिशत सब्सिडी मिलेगी, जो डीज़ल और पैट्रोल वाली खरीदेगा उसे 30 प्रतिशत सब्सिडी दी जाएगी। एक हजार इलैक्ट्रिक बसिज़ के नए रूट, जितने भी विधान सभा सदस्य हैं, आप अपने रूट दीजिए, बसों की कोई समस्या नहीं होगी। माननीय उप-मुख्य मंत्री जी को रूटों के नाम लिखवा देना। हम एक हजार बसों को 30 परसेंट सब्सिडी के तहत युवाओं को रोज़गार के अवसर प्रदान करेंगे।

17.03.2025/1215/AT/ऐ0एस0/3

78. सरकार प्रदेश में ई-वाहनों को बढ़ावा देने के लक्ष्य से पहले चरण में 2025-2026 के दौरान जिला हमीरपुर के सभी सरकारी कार्यालयों में समस्त पारम्पारिक ईन्धन वाले वाहनों के स्थान पर ई-वाहनों को परिवर्तित करने की शुरूआत करेगी।

जलवायु व पर्यावरण

79. सरकार आपदाओं के जोखिमों को कम करने, फसलों के संरक्षण को बढ़ाने, पौष्टिक खाद्य सुरक्षा और ग्रामीण समुदायों को सशक्त बनाने के लिए, राज्य सरकार जल संरक्षण के माध्यम से पिछड़े क्षेत्रों में 100 जलवायु-संवेदनशील गांवों की पहचान कर Climate-Smart Agriculture, और Renewable Energy Micrograids के माध्यम से विकास करने हेतु Climate Resilient Villages (CRV) Programme शुरू करेगी।

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

17.03.2025/1220/md/DC/1

80. सरकार हिमाचल प्रदेश विज्ञान, प्रौद्योगिकी और पर्यावरण परिषद (HIMCOSTE) व समग्र शिक्षा अभियान हिमाचल प्रदेश के सहयोग से चम्बा जिले में चार सरकारी संस्थानों और शिमला जिले में दो सरकारी संस्थानों में Dome Theater स्थापित किए जाएंगे, जिसमें Science और Astronomy शिक्षा तक पहुंच का विस्तार होगा।

81. प्लास्टिक प्रदूषण को कम करने और सर्कुलर इकॉनोमी सिद्धांतों को बढ़ावा देने के लिए राज्य सरकार Deposit Refund System, Buyback Scheme, Advance Recycling सुविधाएं स्थापित करने और Biodegradable विकल्पों को प्रोत्साहित कर 2030 तक प्लास्टिक उन्मूलन के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए "Plastic Neutral Himachal" अभियान शुरू करेगी। प्रदेश में राज्य स्तरीय संग्रह केंद्र स्थापित कर Extended Producer Responsibility (EPR) को लागू किया जाएगा।

82. Himachal Pradesh State Biodiversity Board के साथ सरकार द्वारा Biodiversity Conservation and Protection में युवाओं की भागीदारी को प्रोत्साहित करने हेतु एक Biodiversity Guardianship Program शुरू किया जाएगा। इस कार्यक्रम के तहत सरकार महत्वपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र की सुरक्षा और निगरानी के लिए स्थानीय युवाओं को "Biodiversity Guardian" के रूप में नामित करेगी। इस कार्यक्रम के तहत विभाग युवाओं

को Access Benefit Share Fund के तहत छात्रवृत्ति, प्रशिक्षण और कौशल विकास के अवसरों के माध्यम से प्रोत्साहन प्रदान करेगा।

शिक्षा

83. पिछले 2 वर्षों में हमारी सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में हिमाचल प्रदेश के गठन से लेकर आज तक चली आ रही पुरानी सोच को बदला है। हमने नये शिक्षण संस्थानों को खोलने व उन्हें Upgrade करने के स्थान पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करने को प्राथमिकता दी है। आप सभी जानते हैं कि पिछले कुछ वर्षों में बहुत से शिक्षा संस्थान स्पष्ट सोच अथवा वैज्ञानिक आकलन के आधार पर नहीं खोले गए जिसके कारण पूरे प्रदेश में हजारों शिक्षण संस्थान ऐसे हो गये जिनके दो से तीन किलोमीटर के दायरे में उसी स्तर का दूसरा शिक्षण संस्थान भी काम कर रहा था।

17.03.2025/1220/md/DC/2

इतनी कम दूरी पर एक से अधिक सरकारी शिक्षण संस्थान होने से न केवल अध्यापकों और अन्य संसाधनों का अपर्याप्त इस्तेमाल हो रहा था बल्कि इन सभी संस्थानों में बच्चों की संख्या भी न्यूनतम स्तर तक पहुंच गई। यहां तक कि 412 प्राईमरी स्कूल और 106 मिडल स्कूल जीरो नामांकन (Zero Enrolment) के कारण बन्द हो गये। हमने इस चुनौती को स्वीकार किया और शिक्षा के क्षेत्र की आधारभूत आवश्यकता को समझते हुये शिक्षण संस्थानों का युक्तिकरण किया और स्कूल क्लस्टरों को क्रियाशील किया। पिछले वर्ष मैंने Institutions of Excellence को विकसित करने की बात की थी। प्रदेश में ऐसे शिक्षण संस्थानों को चिन्हित कर लिया गया है तथा इन में अध्यापकों तथा अन्य संसाधनों को चरणबद्ध तरीके से उपलब्ध करवाया जा रहा है। इस पहल से बच्चों की शिक्षा में सुधार देखा गया है। व्यवस्था परिवर्तन की इस प्रक्रिया को आगे भी जारी रखा जायेगा और उच्च शिक्षा संस्थानों का भी युक्तिकरण किया जायेगा।

84. प्रदेश में वर्ष 2001 से लगातार जन्म दर में कमी आई है और हमारी जन्म दर Replacement Level से काफी नीचे आ गई है। इसके परिणाम स्वरूप स्कूल जाने वाले बच्चों की संख्या में काफी कमी आई है। उदाहरण के तौर पर वर्ष 2003 में पहली कक्षा में

भर्ती होने वाले बच्चों की संख्या 1,47,045 थी जो 2023-24 में घट कर 97,427 रह गई। स्वास्थ्य विभाग द्वारा जन्म से सम्बाधित आंकड़े भी यही दर्शाते हैं कि प्रति परिवार बच्चों की संख्या में लगातार कमी आ रही है। इसलिये शिक्षा संस्थानों का पुनर्गठन समय की मांग है।

85. हम प्रदेश के दूरदराज और जनजातीय क्षेत्रों में स्कूलों का युक्तिकरण करते हुए बच्चों को निशुल्क छात्रावास अथवा परिवहन सुविधा उपलब्ध करवा कर Integrated और Composite स्कूल स्थापित करने पर विचार कर रहे हैं। अगले वर्ष इस दिशा में सकारात्मक प्रयास किये जायेंगे ।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

17.03.2025/1225/केएस/डीसी/1

86.सरकार द्वारा लिये गये दूरगामी निर्णयों के कारण प्राथमिक स्तर पर बच्चों में आत्मविश्वास बढ़ा है। सरकार ने सभी स्कूलों को अभिभावकों के साथ मिल कर स्कूलों में वर्दी चुनने का विकल्प दिया। मुझे यह बताते हुये प्रसन्नता है कि प्रदेश में अभी तक 7 हजार 663 विद्यालयों ने अपने बच्चों के लिए मनपसंद वर्दी का चुनाव किया है।

87. हिमाचल देश का पहला राज्य है जहां गांव के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले मेधावी छात्र-छात्राओं और खेलकूद तथा सांस्कृतिक क्षेत्रों में उत्कृष्ट उपलब्धियां प्राप्त करने वाले बच्चों को विदेश में शैक्षणिक भ्रमण पर भेजा गया है।

88. वर्ष 2025-2026 से प्रदेश के सभी सरकारी स्कूलों में बच्चों और अध्यापकों की Digital Attendance शुरू की जाएगी।

89. प्रदेश में 19 स्थानों पर राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल बनाए जा रहे हैं। इनके निर्माण के लिए 31 करोड़ रूपये जारी कर दिए गए हैं। मैं निम्नलिखित स्थानों पर वर्तमान में कार्य कर रहे Government Senior Secondary Schools को प्रथम चरण में राजीव गांधी डे-बोर्डिंग स्कूल के रूप में विकसित करने की घोषणा करता हूं :

गगरेट, अम्ब, हरोली, बंगाणा, बड़सर, सुजानपुर, धर्मशाला, ज्वाली, इन्दौरा, सरकाघाट, हमीरपुर, भोरंज, बड़ा, नादौन, घुमारवीं, देहरा, जयसिंहपुर, शाहपुर, भटियात, फतेहपुर, पालमपुर, अर्की, सिराज, ढलियारा, शिलाई, रिकांगपिओ (किन्नौर), केलांग, ठियोग, नगरोटा, कुल्लू और जोगिन्द्रनगर। इसके अतिरिक्त प्रत्येक विधानसभा में प्री-नर्सरी से 12वीं कक्षा तक कम से कम 750 बच्चों वाले स्कूलों को भी डे बोर्डिंग स्कूलों के मापदण्डों पर विकसित किया जाएगा। हम सारे विधान सभा क्षेत्रों में ऐसे स्कूल बना रहे हैं।

90. शिक्षा के क्षेत्र में बेहतर प्रबंधन के लिए शिक्षा निदेशालयों का पुनर्गठन किया जाएगा। स्कूल शिक्षा के लिए एक अलग निदेशालय बनाया जायेगा और कॉलेज तथा उच्च शिक्षा से जुड़े विषयों को देखने के लिए एक अलग निदेशालय का गठन किया जाएगा।

91. अध्यक्ष महोदय, मैं पिछले दिनों सुजानपुर गया और वहां के सैनिक स्कूल के होस्टल की हालत देखी। वहां पर 70 प्रतिशत बच्चे हिमाचल के पढ़ते हैं और साढ़े चार सौ ऑफिसर्ज़ वह सैनिक स्कूल हमें देता है। 21 ऑफिसर्ज़ इस बार वहां से सिलेक्ट हुए। क्योंकि उसका सारा कंट्रोल मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस का है और खर्चा हिमाचल प्रदेश सरकार उठाती है। उनके होस्टल की हालत बहुत दयनीय थी। मैं सुजानपुर स्थित सैनिक

17.03.2025/1225/केएस/डीसी/2

स्कूल को Hostel की मरम्मत के लिए 3 करोड़ रूपये की राशि दिए जाने की घोषणा करता हूं।

92. प्रदेश में लड़कियों की शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए ऊना और कांगड़ा में कॉलेज की छात्राओं के लिए चार Hostel बनाए जाएंगे। साथ ही हमीरपुर और सुजानपुर में स्कूली लड़कियों के लिए Hostel बनाए जाएंगे।

93. H.P. State Higher Education Council राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2020 के विभिन्न प्रावधानों का अध्ययन करके प्रदेश में उनके चरणबद्ध क्रियान्वयन के लिए एक कार्य योजना तैयार करेगी।

शिक्षा के क्षेत्र में कुल 9 हजार 849 करोड़ रूपये प्रस्तावित हैं।

तकनीकी शिक्षा

94. उत्कृष्टता की हमारी निरंतर खोज और नवाचार की संस्कृति विकसित करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं। मुझे तकनीकी शिक्षा के क्षेत्र में अत्याधुनिक विचारों और पहलों को शुरु करने के लिए 2 करोड़ रुपये के समर्पित Innovation Fund की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है।

95. अध्यक्ष महोदय, आगामी वित्तीय वर्ष में राजकीय हाईड्रो इन्जीनियरिंग महाविद्यालय बन्दला में एम.टेक इलैक्ट्रिकल इंजीनियरिंग (Electrical Vehicle Technology) की कक्षाएं चलाई जाएंगी।

96. जिला बिलासपुर के घुमारवीं में Digital University of Innovation, Entrepreneurship, Skill, and Vocational Studies की स्थापना सार्वजनिक-निजी भागीदारी (PPP Mode) व Self Financing पर की जाएगी, जो एक डिजिटल रूप से कुशल और उद्यमशील कार्यबल को बढ़ावा देगी। यह विश्वविद्यालय Innovation का केंद्र बनेगा और हमारे युवाओं को Competitive Global Environment के लिए आवश्यक कौशल प्रदान करेगा।

सड़कें व पुल

97. अध्यक्ष महोदय, हिमाचल प्रदेश जैसे पहाड़ी राज्य में विशेष रूप से रेलवे और जल परिवहन के पर्याप्त नेटवर्क की अनुपस्थिति में एक मजबूत Road Network बहुत जरूरी है। अतः हमारी सरकार इस महत्वपूर्ण क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता प्रदान करना जारी रखेगी। **अ0व0 द्वारा जारी**---

17.03.2025/1230/av/hk/1

मुख्य मंत्री क्रमागत----------

98. मेरी सरकार 345 करोड़ रूपये की लागत से निम्न 6 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं का 2025-2026 में निर्माण कार्य शुरू करेगी :-

- नवगांव-बेरी

- सुजानपुर-टीहरा-सन्धोल
- हवल-हडसर-देहरी-पनाल्ठ-धार जरोट-नगरोटा
- सूरियां-बरियाल-देहरा-ज्वाली और गज खड्ड के ऊपर पुल
- बखरोट-करसोग-सनारली-सैंज
- टिक्कर जड़ोल-घान-ननखड़ी-खमाडी
- कुफरी-चैल

99. इसके अतिरिक्त NABARD के तहत भी 498.62 करोड़ रुपये की लागत से 50 सड़कों एवं पुलों की परियोजनाओं की स्वीकृति प्राप्त कर ली गई है।

100. मेरी सरकार द्वारा सभी कार्यों में खरीद के लिए e-Tender को प्रभावी बनाया है। इसमें निविदाओं के प्रकाशन की अवधि 14 दिन से घटाकर 7 दिन कर दी गई है तथा कार्यों को Award करने का कुल समय जो पहले औसत 37 दिन था, अब 12 दिन हो गया है, जिससे कार्य आवंटन तथा निष्पादन में तेजी आएगी।

101. वर्ष 2025-2026 के लिए "मुख्य मन्त्री सड़क योजना" के अन्तर्गत 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

102. अध्यक्ष महोदय, सुशासन के लिए स्वच्छ प्रशासन आवश्यक है। 2025-2026 के दौरान राजस्व विभाग का व्यापक Digitalization करके राजस्व सम्बन्धी सभी मामलों के शीघ्र निपटान के साथ-साथ पूरी प्रक्रिया में अच्छे शासन के लिए पारदर्शिता सुनिश्चित की जाएगी। इस दिशा में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं :-

17.03.2025/1230/av/hk/2

- सभी राजस्व न्यायालयों को चरणबद्ध तरीके से डिजिटल किया जाएगा तथा प्रदेश में ई-राजस्व प्रणाली लागू की जाएगी। Revenue Court Management System (RMS) के अन्तर्गत एक मॉड्यूल विकसित किया जाएगा जो नागरिकों से सम्बन्धित भूमि रिकॉर्ड को सीमांकन और नामान्तरण से जुड़े मामलों के साथ मैप करेगा। इससे न केवल नागरिकों को राजस्व मामले डिजिटल तरीके से File करने

में मदद मिलेगी बल्कि राजस्व अधिकारियों को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर अदालती कार्रवाई करने में भी मदद मिलेगी।

- नवीनतम हवाई सर्वेक्षण तकनीक (Aerial Survey Technology) के माध्यम से चयनित शहरी क्षेत्रों में वास्तविक जमीनी स्थिति के अनुसार राजस्व रिकॉर्ड तैयार किया जाएगा जिससे बेहतरीन शहरी नियोजन में मदद मिलेगी।

- डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से ततीमा (Maps) उपलब्ध करवाने हेतु "भू-नक्शा" एप्लीकेशन का उपयोग किया जाएगा, जिससे लोगों को अपने Maps प्राप्त करने के लिए कार्यालयों में जाने की आवश्यकता नहीं होगी। उसको जमाबंदी, ततीमा इत्यादि सब कुछ ऐप पर उपलब्ध हो जाएगा।

103. सरकार ऑनलाइन म्यूटेशन सॉफ्टवेयर शुरू करके म्यूटेशन की प्रक्रिया को डिजिटल करेगी, जिससे इस प्रक्रिया की एक पेपरलेस प्रणाली स्थापित होगी। इससे सार्वजनिक सेवा वितरण में सुधार होगा और म्यूटेशन को सत्यापित करने में होने वाली अनावश्यक देरी भी कम होगी।

104. आपदाओं से निपटने के लिए 3,645 पंचायतों में एक संगठित और सामुदायिक संचालित "पंचायत आपातकालीन प्रतिक्रिया केन्द्र" की स्थापना की जाएगी। यह केन्द्र अन्तर जिला एजेन्सी समूह, समन्वय केन्द्रों और स्थानीय अधिकारियों के साथ मिलकर काम करेगा ताकि समय रहते आपदा से निपटने की तैयारी की जा सके।

105. सरकार ने AFD के माध्यम से लगभग 892 करोड़ रुपये की लागत से आगामी पांच वर्षों के लिए Disaster Risk Reduction and Preparedness Project बनाया है। यह महत्वाकांक्षी परियोजना आपदाओं से निपटने और उनकी प्रभावशीलता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस परियोजना के मुख्य बिन्दु निम्नलिखित हैं :-

17.03.2025/1230/av/hk/3

- Multi Hazards जैसे की Landslides, Flash Floods, Clould Burst, GLOF इत्यादि के लिए Early Warning System का विकास और GIS पर आधरित Decision Support System 1
- राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (State Disaster Response Force) के परिसरों की स्थापना।
- भूस्खलन रोकने और ढलानों को स्थिर करने के लिए Bio-Engineering उपायों का प्रोत्साहन ।
- उप-मण्डल और तहसील स्तर पर भी "Disaster Risk Reduction Co-ordination Centre" स्थापित किए जाएंगे।
- HP State Disaster Management Authority, District Disaster Management Authorities, State Emergency Operation Cell, District Emergency Operation Cells को सुदृढ़ किया जाएगा।
- कृषि और बागवानी के लिए जलवायु/मौसम पूर्वानुमान का विकास ।
- जंगल की आग के खतरों को कम करने के लिए गतिविधियों को बढ़ावा।
- जलवायु परिवर्तन और अनुकूलन से सम्बन्धित अध्ययन ।
- भूकंप-प्रतिरोधी तकनीकों को बढ़ावा देना।
- Disaster Risk Reduction के लिए सूचना प्रौद्योगिकी का विकास।
- Himalayan Disaster Risk Reduction Centre की स्थापना पालमपुर में की जाएगी।

सामाजिक कल्याण

106. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश वासियों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना मेरी सरकार की प्राथमिकताओं में से एक है। हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य की अवधारणा के अनुसार कार्य करने में विश्वास करती है। इस क्षेत्र को और मजबूत करने के लिए मैं निम्न घोषणाएं करता हूं :-

टी सी द्वारा जारी

17.03.2025/1235/टी0सी0वी0/एच0के0-1

मुख्य मंत्री .... जारी

- मैं निम्न घोषणा करता हूं कि वर्तमान में प्रदेश में आठ पेंशन योजनाएं सामाजिक सुरक्षा के क्षेत्र में कार्य कर रही है जिन पर चालू वित्तीय वर्ष के दौरान 1,410 करोड़ पर खर्च किए गए हैं और जिनसे 8,24,928 व्यक्ति लाभान्वित हुए हैं। वर्ष 2025-26 के दौरान सामाजिक सुरक्षा पेंशन में 37000 नये लाभार्थियों को शामिल किया जाएगा तथा इसके लिए लगभग 67 करोड़ रुपये का अतिरिक्त व्यय किया जाएगा।
- सरकारी कर्मचारी/पेंशनभोगियों और आयकर दाता दिव्यांगजनों को छोड़कर सभी विशेष योग्यजन व्यक्तियों (दिव्यांगजन) जिनकी बैंचमार्क विकलांगता 40 प्रतिशत या अधिक है उनको सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना (SSP) प्रदान की जाएगी। सरकार का या कदम दिव्यांगजनों को न केवल आर्थिक सुरक्षा सुनिश्चित करवाएगा अपितु उन्हें गरिमापूर्ण जीवन जीने के लिए भी सशक्त करेगा।
- सामाजिक सुरक्षा पेंशन (SSP) के वितरण के लिए पारदर्शिता और इसे प्रभावी बनाने के लिए आगामी वित्त वर्ष में एक End -to-End एकीकृत ऑनलाइन पोर्टल/प्लेटफार्म लॉन्च किया जाएगा। इसके माध्यम से हिम परिवार, रजिस्टर नकल, राजस्व रिकॉर्ड, आय प्रमाण पत्र आदि को ऑनलाइन लिंक किया जाएगा। इसी के माध्यम से ग्रामीण विकास विभाग, शहरी विकास विभाग और Himachal Pradesh Building and Other Construction Workers Welfare Board (HPBOCW) ls एन0ओ0सी0 प्राप्त करने की सुविधा भी प्राप्त होगी।

107. सरकार द्वारा शुरू की गई "**इंदिरा गांधी प्यारी बहना सुख सम्मान निधि' योजना**" के तहत 18 से 59 वर्ष आयु वर्ग की पात्र महिलाओं को चरणबद्ध तरीके से 1500 रुपये प्रति माह प्रदान किए जाते हैं। राज्य की संपदा के लाभों से वंचित सभी वर्गों को लाभ पहुंचाने के

लिए हमारी सरकार कृत संकल्प हैं। इस उद्देश्य से आगामी वित्त वर्ष में, इस योजना का चरणबद्ध तरीके से विस्तार करते हुए 1 जनवरी, 2025 से 31 मार्च, 2026 के बीच 21 साल की उम्र प्राप्त करने वाली हर पात्र बेटी को, हर महीने

17.03.2025/1235/टी0सी0वी0/एच0के0-2

1500 रुपये इस योजना में दिए जाएंगे। इसके अतिरिक्त जो भी महिलाएं दूसरों के घरों में काम करके अपने परिवार का गुजारा करती है। कई महिलाएं डॉमेस्टिक सर्वेंट्स हैं, उनके लिए कोई पैरामीटर नहीं है। उन्हें भी इस योजना के अंतर्गत 1 जून, 2025 से लाभ मिलना शुरू हो जाएगा। उनकी पात्र बेटियां भी 1500 रुपये मिलने की हकदार होगी। आने वाले समय में जो भी महिलाएं पंचायत द्वारा अनुमोदित की गई है, उनको चरणबद्ध तरीके से इस योजना से लाभान्वित किया जाएगा। विधवा बहनों की पात्र बेटियां भी इस योजना के अंतर्गत लाभ पाने की पात्र होगी। इसके अतिरिक्त यदि विधवा बहनों की बेटियां प्रोफेशनल कोर्सिज के लिए पढ़ाई करना चाहे तो सरकार उनकी पूरी फीस और संस्थान द्वारा स्वीकृत होटल फीस का व्यय वहन करेगी। यदि वह पी0जी0 में रहना चाहती है तो सरकार एक वर्ष में 10 माह के लिए 3000 रुपये प्रति माह प्रदान करेगी। इस योजना के अंतर्गत आगामी वित्त वर्ष के दौरान 200 करोड़ रुपये का व्यय किया जाएगा।

विधवा बहनों की बेटियां डॉक्टर बनना चाहती है लेकिन डॉक्टर की फीस बहुत होती है, हॉस्टल की फीस बहुत होती है। लेकिन कई डॉक्टर इंजीनियर बेटियां पी0जी0 में रहना चाहती है। हमारी सरकार उन विधवा बहनों की बेटियों को भी 3000 रुपये प्रतिमाह पी0जी0 का देगी।

108. मैं Institution for Childern with Special Abilities (ICSA) सुंदर नगर की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य कल्याण परिषद् की ओर से विशेष योग्यजन बच्चों के लिए संस्थान आई0सी0एस0ए0, ढली को कर्मचारियों सहित सरकार के अधीन लाने की घोषणा करता

हूं । इस कदम का लक्ष्य यह है कि इन बच्चों को और विकसित सुविधाएं प्रदान की जा सकें।

109 एन0एस0 द्वारा ... शुरू

17-03-2025/1240/NS-YK/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

109. सरकार द्वारा स्वर्ण जयंती आश्रय योजना (SJAY) के तहत अनुसूचित जाति, जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के बेघर पात्र व्यक्तियों को नए मकान के निर्माण के लिए 1.50 लाख रुपये की वित्तीय सहायता दी जाती है। निर्माण लागत और इन्फ्लेशन को देखते हुए, सरकार इस योजना के अंतर्गत गृह निर्माण के लिए अन्य योजनाओं से समन्वय करते हुए अतिरिक्त संसाधन उपलब्ध करवाएगी।

110. सरकार द्वारा समाज में छुआछूत की प्रथा को दूर करने के उद्देश्य से अन्तर्जातीय विवाह के लिए मिलने वाली प्रोत्साहन राशि को 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये किया जाएगा।

111. सरकार "**विकलांगता व्यक्तियों के विवाह के लिए प्रोत्साहन**" नामक उप योजना के तहत 70 प्रतिशत से अधिक विकलांगता वाले दिव्यांगजनों के विवाह हेतु विवाह प्रोत्साहन राशि 50,000 रुपये से बढ़ाकर 2 लाख रुपये करेगी।

112. सरकार द्वारा "**मुख्यमंत्री विधवा एवं एकल नारी आवास योजना**" के तहत आगामी वर्ष में नए लाभार्थियों को शामिल करने का लक्ष्य रखा है, जिस पर 5 करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान किया जाएगा।

113. सरकार वर्तमान में विविध "**वृद्धजनों के लिए एकीकृत योजना**" के अंतर्गत 9 वृद्ध आश्रम चला रही है। इस योजना को आगे बढ़ाते हुए वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश के अन्य स्थानों पर निजी क्षेत्र की भागीदारी से वृद्ध आश्रम/ वरिष्ठ नागरिक गृह स्थापित किए जाएंगे।

114. मैं हिमाचल प्रदेश अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति विकास निगम के माध्यम से स्वरोजगार और विभिन्न लघु उद्यमों आदि के लिए कम ब्याज पर वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए परिवार की निर्धारित वार्षिक आय को मौजूदा 35,000 रुपये से बढ़ाकर 50,000 रुपये करने की घोषणा करता हूं।

115. सरकार वर्तमान में राज्य में जिला कुल्लू में दो व हमीरपुर, ऊना और कांगड़ा में एक-एक इंटीग्रेटेड नशा मुक्ति केंद्र चला रही है। राज्य में ड्रग एडिक्शन और

17-03-2025/1240/NS-YK/2

तस्करी की बढ़ती समस्याओं को देखते हुए और अधिक ऐसे केंद्रों की आवश्यकता है, जिसके लिए वित्तीय वर्ष 2025-26 में राज्य में तीन और नशा रोकथाम एवं नशा मुक्ति-सह-पुनर्वास केंद्र स्थापित किए जाने प्रस्तावित हैं।

महिला एवं बाल विकास

116. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार महिलाओं के सामाजिक, आर्थिक, स्वास्थ्य एवं पोषण और बच्चों के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक और पोषण संबंधी स्थिति में सुधार लाने हेतु वचनबद्ध है।

117. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह कहते हुए हर्ष हो रहा है कि प्रदेश में Sex Ratio at Birth में लगातार सुधार हो रहा है तथा वर्ष 2023 में 947 के मुकाबले यह वर्ष 2024 में 964 हो गया। यह सरकार द्वारा इस क्षेत्र में किए गए या किया जा रहे निरंतर प्रयासों तथा चलाई जारी विभिन्न योजनाओं के सफल क्रियान्वयन का परिणाम है। महोदय, मैं बीपीएल परिवारों में जन्म लेने वाली दो बालिकाओं के लिए "**इंदिरा गांधी सुख शिक्षा योजना**" की घोषणा करता हूं। यह "**बेटी है अनमोल योजना**" को और अधिक सशक्त करेगी। इसमें बालिका के जन्म पर 25,000 रुपये की राशि बीमा कम्पनी में जमा करने की व्यवस्था होगी, साथ ही बालिका के माता-पिता को बालिका के जन्म पर जीवन बीमा का लाभ भी देय होगा जोकि

प्रति अभिभावक दो लाख रुपये होगा। बीमा की मैच्योरिटी पर देय राशि बालिका को 18 या उसकी स्वेच्छा से 27 वर्ष की आयु तक दिए जाने का प्रावधान होगा।

118 पैरा आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

17.03.2025/1245/RKS/वाईK-1

118. अध्यक्ष महोदय, काम-काजी महिलाओं की आवासीय जरूरतों को पूरा करने के उद्देश्य से वर्ष 2025-2026 में 132 करोड़ रुपए की लागत से क्रमशः सोलन, नीरी, दरुही, पालमपुर, लुथान, बद्दी, गगरेट, नगरोटा बगवां, चनौर इंडस्ट्रियल एरिया और मेडिकल डिवाइस पार्क सोलन में कुल 13 Working Womens' Hostels का निर्माण कार्य आरम्भ किया जाएगा।

119. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार की प्राथमिकता बच्चों की शिक्षा में गुणात्मक सुधार लाने की है। इस दृष्टि से बच्चों में शिक्षा की नींव को सुदृढ़ करने के लिए सरकार प्रयासरत है। इसी कड़ी में मैं 1 अप्रैल, 2025 से सभी 18,925 आंगनवाड़ी केंद्रों को "आंगनवाड़ी सह प्री-स्कूल" के रूप में नामित करने की घोषणा करता हूँ। इन आंगनवाड़ी केंद्रों को नजदीकी स्कूलों में यथासंभव Co-locate किया जाएगा। इन स्कूलों में तीन से छह वर्ष के बच्चों को खेल-खेल में शिक्षा प्रदान की जाएगी। यह शिक्षा आंगनवाड़ी कार्यकर्ता द्वारा SCERT सोलन द्वारा विकसित पूर्व प्राथमिक पाठ्यक्रम तथा National Institute of Public Cooperation and Child Development (NIPCCD) नई दिल्ली द्वारा विकसित आधारशिला राष्ट्रीय पाठ्यक्रम के अनुसार प्रदान की जाएगी।

120. माननीय अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में चिकित्सा सुविधाओं में हुई व्यापक वृद्धि के बावजूद छोटे बच्चों के स्वास्थ्य मानकों में आ रही गिरावट के कारणों को समझने की दृष्टि से सरकार ने पिछले दिनों एक व्यापक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें चर्चा उपरान्त देश के शीर्ष विशेषज्ञों ने अपने निष्कर्ष और सिफारिशें प्रस्तुत की। कार्यशाला में यह तथ्य सामने आए कि युवा महिलाओं के बीच छोटे बच्चों के समुचित ब्रेस्टफीडिंग और पूरक

भोजन तकनीकों के बारे में जागरूकता की कमी है। साथ ही इन सिफारिशों को आकार देने के लिए स्वास्थ्य विभाग और महिला एवं बाल विकास निदेशालय के बीच बेहतर समन्वय भी आवश्यक है। इसके अतिरिक्त प्रदेश में वर्षों से चल रहे पूरक पोषाहार कार्यक्रम में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है। अतः मैं इस कार्यक्रम को और अधिक सुदृढ़ बनाने हेतु एक नई योजना "इंदिरा गांधी मातृ शिशु संकल्प योजना" की घोषणा करता हूं।

121. इस योजना के अन्तर्गत हर आंगनवाड़ी में पूरक पोषाहार को और अधिक पौष्टिक बनाने हेतु विशेषज्ञों की राय से पूरक पोषाहार को लाभार्थियों में आबंटित किया जाएगा। साथ ही यह भी सुनिश्चित किया जाएगा कि जहां तक सम्भव हो पूरक पोषाहार का क्रय विकेंद्रीकृत किया जाएगा। इस पर प्रतिवर्ष 65 करोड़ रुपये अतिरिक्त धनराशि व्यय होगी। अभी तक स्टेट लैवल पर राशन की खरीद की जा रही है जिससे राशन को आंगनवाड़ी केंद्रों तक पहुंचाने में समय लग जाता है। हम इस योजना का विकेन्द्रीकरण कर राशन की खरीद की पावर जिला स्तर को निहित कर रहे हैं ताकि वे अपने स्तर पर अच्छा राशन खरीद कर आंगनवाड़ी केंद्रों को मुहैया करवा सकें। इसके अतिरिक्त स्वास्थ्य, जल शक्ति, ग्रामीण विकास तथा शिक्षा विभाग में वर्तमान में चल रहे सम्बन्धित कार्यक्रमों में सामंजस्य स्थापित कर एक समेकित कार्यक्रम चलाने की दृष्टि से एक Co-ordination कमेटी का गठन किया जाएगा। फील्ड लेवल पर आशा वर्कर व आंगनवाड़ी वर्कर के बीच भी बेहतर तालमेल बैठाया जाएगा व उनके द्वारा किए जा रहे Data Collection को पारस्परिक संवाद द्वारा अधिक उपयोगी बनाया जाएगा। कुपोषण, एनीमिया, निमोनिया व डायरिया तथा अन्य जल जनित रोगों की रोकथाम के साथ-साथ सभी स्टेकहोल्डर की जागरूकता, आउटरीच और प्रशिक्षण पर केंद्रित एक विशेष अभियान चलाया जाएगा।

122. सरकार नीति आयोग के साथ मिलकर जिला ऊना में पायलट आधार पर चलाए जाने वाले WINGS प्रोजैक्ट (World-leading Innovative Study Programme) को पूरा

सहयोग देगी ताकि हमारी महिलाओं व बच्चों के लिए एक स्वस्थ भविष्य का निर्माण संभव हो सके।

सामाजिक सुरक्षा, महिला, बाल, एवं अन्य पिछड़ वर्गों के कल्याण के लिए कुल 2 हजार 533 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

आयुष

123. अध्यक्ष महोदय, स्वास्थ्य के क्षेत्र में आयुष विभाग की महत्वपूर्ण भूमिका है। आयुष केवल एक चिकित्सा पद्धति ही नहीं है बल्कि प्राकृतिक जीवनशैली का एक तरीका भी है। अतः आम जनता को इस सुविधा का लाभ प्रदान करने के लिए हमारी सरकार बहुत से कार्य कर रही है।

124. हमारी सरकार आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान जिला कांगड़ा में 50 बिस्तरों वाले एकीकृत आयुष अस्पताल का निर्माण कार्य शुरू करेगी।

125. पायलट आधार पर पपरोला और शिमला के आयुष अस्पतालों में पर्यटकों और आम जनता के लिए वैलनेस पंचकर्मा शुरू किया जाएगा।

श्री बी0एस0द्वारा... जारी

17.03.2025/1250/बी.एस./ए.जी./-1

मुख्य मंत्री जारी...

126 मैं 'आचार्य चरक योजना' की शुरूआत करता हूं, जिसके तहत हिमाचल प्रदेश के सभी सरकारी आयुष अस्पतालों और औषधालयों में मरीजों को निःशल्क जांच और आवश्यक दवाइयां उपलब्ध करवाई जाएंगी। इस योजना के अन्तर्गत 20 प्रकार की निःशल्क नैदानिक जांच तथा आवश्यक औषधि सूची में शामिल 150 से अधिक आयुष

दवायें निशुल्क प्रदान की जाएगी। इससे प्रदेश के नागरिकों को गुणवत्ता पूर्ण पारंपरिक चिकित्सा सेवा मिलेगी और यह एक स्वस्थ समाज के निर्माण में योगदान देगा।

पुलिस/कानूनी व्यवस्था एवं अग्निशमन

127 अध्यक्ष महोदय, कानूनी एवं व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने हेतु हमारी सरकार प्रयासरत है। एच0पी0 एंटी ड्रग एक्ट के प्रावधानों के माध्यम से वर्तमान समय में नशे से जूझ रहे लोगों के लिए प्यूनिटिव मेजर्स के स्थगन पर पुनर्वास पर जोर दिया जाएगा। ताकि उन्हें समाज की मुख्य धारा में लाया जा सके। नशीली दवाओं के दुरुपयोग और तस्करी करने वालों के साथ शक्ति से निपटा जाएगा।

128 मैं वर्ष 2025-26 में स्पेशल टास्क फोर्स बनाने की घोषणा करता हूं जिसके माध्यम से प्रदेश सरकार नशीले पदार्थ की तस्करी से संबंधित गतिविधियों पर विराम लगाने हेतु कार्य करेगी।

129 संगठित अपराध सिंडिकेट या गिरोह द्वारा गैर कानूनी गतिविधियों की रोकथाम और नियंत्रण से निपटने के लिए एक विशेष प्रावधान के तहत एक अधिनियम Himachal Pradesh Prevention of Continuing Unlawful Activity and Control of Organized Crime Act, 2025 इस सदन में लाया जाएगा।

130 पर्यटक सुरक्षा में सुधार एवं पुलिस जवानों के प्रभावी विकास तथा आधुनिक आपराधिक जांच की दृष्टि से विश्व प्रसिद्ध पर्यटक स्थल में पुलिस स्टेशनों/डैस्क को स्थापित किया जाएगा और संबंधित थानों के साथ एकीकृत किया जाएगा।

131 अध्यक्ष महोदय, अग्निशमन विभाग में अग्निशमन सेवाओं का आधुनिकीकरण एवं विस्तार परियोजना के अंतर्गत अगले चरण में 21 करोड़ पर के व्यय के साथ में निम्नलिखित घोषणाएं करता हूंः-

- राजगढ़, जिला सौलन, कण्डाघाट, जिला सोलन, में दमकल केन्द्र खोले जाएंगे।

- नदौन, इंदौर, राजगढ़ और कण्डाघाट में आठ नए अग्निशमन वाहनों को क्रय करने और 20 से 22 वर्ष पुराने 60 अधिवेशन वाहनों के स्थान पर चरणबद्ध तरीके से नए वाहनों को खरीदा जाएगा।
- 16 Quick Response Vehicles, प्रशिक्षण और जन समुदाय को जागरूकता प्रदान करने के लिए दो बसें और विभिन्न प्रकार के अग्निशमन उपकरणों को खरीदा जाएगा।

132. वर्ष 2025-26 के दौरान उप दमकल केंद्र काजा व कुमारसेन, जोगिन्द्रनगर, फतेहपुर व अन्य दमकल चौकियों के विभागीय भवनों का निर्माण किया जाएगा।

उद्योग

133 अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार प्रदेश में उद्योगों को बढ़ावा देने के प्रति कृत संकल्प है। वर्ष 2024-25 में बल्ब ट्रक पार्क में 234 करोड़ रुपए की राशि के निर्माण कार्य को स्वीकृति दी गई है। आगामी वर्ष में इस परियोजना के कार्य को सुचारू रखने के लिए केंद्र सरकार के अनुदान के अतिरिक्त आवश्यकता अनुसार बजट का प्रावधान किया जाएगा।

134 प्रदेश में बरसात के कारण बनी प्रतिकूल परिस्थितियों के बावजूद वर्ष 2024-25 में 149 औद्योगिक प्रस्तावों को सैद्धांतिक मंजूरी प्रदान की गई जिससे 3,084 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा तथा 15,000 लोगों को रोजगार मिलेगा। वर्ष 2025-26 के दौरान प्रदेश के औद्योगिक नीति में मूलभूत बदलाव किए जाएंगे। निवेशकों के लिए सभी औपचारिकताओं को न्यूनतम स्तर पर रखा जाएगा तथा सभी आवश्यक क्लीयरेंस दो माह के भीतर सुनिश्चित की जाएगी। निवेशकों के लिए एक फ्रेंडली एनवायरनमेंट बनाने में सरकार केवल Enabler का रोल निभाएगी। हरित ऊर्जा, सौर ऊर्जा, दुग्ध उत्पादन व इलेक्ट्रिकल व्हीकल जैसे क्षेत्रों में निवेश को आकर्षित करने हेतु आगामी वित्तीय वर्ष में इन्वेस्टर आउटरिच प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा।

135 हमारी सरकार सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों को सुदृढ़ बनाने के लिए कृत संकल्प है। इस कड़ी में रेसिंग एंड एक्सीलरेटिंग एस0एम0एस0ई0 स्कीम्स के अंतर्गत 1,642 करोड़

रुपए की लागत से कार्यक्रम के पहले चरण में 109 करोड़ रुपए की योजना का निष्पादन कार्य प्रगति पर है।

136 मेरी सरकार राज्य की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी उद्योगपतियों, छोटे माध्यम व बड़े उद्योगों की पूरी सराहना करती है। सरकार इस बात से भी भलीभांति परिचित कि एक समृद्ध हिमाचल केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की ताकत पर ही निर्मित हो सकता है। मुझे पता है कि उद्योगों और उद्यमियों को निवेश के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है। जिसमें से कुछ केवल प्रोसिजरल है व शीघ्र ही हल किए जा सकते हैं। अतः सभी हितकारकों को एक मंच पर नियमित रूप से मिलकर स्थिति की समीक्षा करने और व्यवसाय को सरल बनाने के लिए एक इंस्टीट्यूशनलाइज्ड डायलॉग मेकैनिज्म की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूं कि एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सभी पहलुओं पर विचार करेगा, नियमित रूप से बैठकें और सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेगा।

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.05.2025/1255/DT/AG/1

136. मेरी सरकार राज्य की विकास यात्रा में योगदान देने वाले सभी उद्योगों, उद्योगपतियों, छोटे, मध्यम व बड़े उद्यमियों की पूरी सराहना करती है। सरकार इस बात से भी भली-भान्ति परिचित है कि एक समृद्ध हिमाचल केवल राज्य के औद्योगिक क्षेत्र के विस्तार की ताकत पर ही निर्मित हो सकता है। मुझे पता है कि उद्योगों और उद्यमियों को निवेश के दौरान विभिन्न समस्याओं का सामना करना पड़ता है, जिनमें से कुछ केवल Procedural हैं व शीघ्र ही हल किए जा सकते हैं। अतः सभी हितधारकों को एक मंच पर नियमित रूप से मिलकर स्थिति की समीक्षा करने और व्यवसाय को सरल बनाने के लिए एक Institutionalised Dialogue Mechanism की आवश्यकता है। मैं घोषणा करता हूँ कि एक उच्च स्तरीय बोर्ड गठित किया जाएगा, जो राज्य के औद्योगिक क्षेत्र से सम्बन्धित सभी

पहलुओं पर विचार करेगा, नियमित रूप से बैठकें करेगा और सभी मुद्दों को प्रभावी ढंग से हल करेगा।

137. पिछले दो वर्षों में मेरी सरकार ने दिल्ली हाट में सर्दियों के महीनों के दौरान हिम उत्सव का आयोजन किया है, जो उल्लेखनीय सफलता के साथ संपन्न हुआ। इसने हिमाचल के उत्पादों को दिल्ली के high paying clientele of Delhi से परिचित कराया है। परिणाम उत्साहजनक हैं, जिससे ग्रामीण कारीगरों को परिपक्व लाभ प्राप्त हुआ है। मैं घोषणा करता हूँ कि हिम उत्सव एक वार्षिक आयोजन होगा।

138. पिछले वर्ष उद्योगों को दी जाने वाली सब्सिडी को एक रूपये प्रति यूनिट की दर से Withdraw किया गया था। में 66 KV या उससे अधिक सप्लाई वोल्टेज पर चलने वाले उद्योगों को राहत देने के लिए 40 पैसे प्रति यूनिट बिजली की खपत पर सब्सिडी देने की घोषणा करता हूँ। यह सब्सिडी वर्ष में दो बार अक्टूबर और मार्च के महीने में DBT के माध्यम से दी जाएगी।

जनजातीय विकास

139. हिमाचल प्रदेश सरकार जनजातीय क्षेत्रों और यहां के लोगों की समस्याओं के प्रति पूरी तरह जागरूक और संवेदनशील है। प्रदेश सरकार के सतत् प्रयासों से हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में अभूतपूर्व विकास हुआ है। आज जनजातीय क्षेत्रों में दूसरे भागों से अधिक सम्पन्नता और समृद्धि देखी जा सकती है। हमारे जनजातीय क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति आय का औसत प्रदेश के अन्य जिलों से अधिक है। इन क्षेत्रों में न केवल आर्थिक सम्पन्नता है अपितु सामाजिक दृष्टि से भी ये क्षेत्र प्रदेश में अग्रणी है।

17.05.2025/1255/DT/AG/2

इन क्षेत्रों में जन्म के समय लिंगानुपात प्रदेश के अन्य भागों से अच्छा है। मैं प्रदेश के जनजातीय लोगों को इन तमाम उपलब्धियों के लिए बधाई देता हूँ।

140. सोलर ऊर्जा में स्वरोजगार के अवसर सृजित करने के लिए सरकार जनजातीय क्षेत्रों तथा बड़ा भंगाल, डोडरा क्वार, कुपवी, तीसा और अन्य चिन्हित स्थानों पर निजी क्षेत्र में

250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सोर परियोजना स्थापित करने के लिए 5 प्रतिशत का ब्याज उपदान प्रदान करेगी। यानि अगर कोई ट्राईबल एरिया में बैंक से लोन लेकर अगर 100 या 150 किलोवाट का सोलर पावर प्रोजेक्ट लगाता है और उसमें बैंक के द्वारा रेट ऑफ इंटरस्ट 9 या 10 प्रतिशत लगाया जाता है तो उस इंटरस्ट का 5 प्रतिशत सरकार वहन करेगी। गैर जनजातीय क्षेत्रों में 250 किलोवाट से एक मेगावाट तक की सोलर परियोजनाओं पर 4 प्रतिशत तथा एक मेगावाट से बड़ी परियोजनाओं पर हिमाचली युवाओं को 3 प्रतिशत ब्याज उपदान दिया जाएगा।

141. वन अधिकार अधिनियम, 2006 के क्रियान्वयन को प्राथमिकता के आधार पर किया जाएगा, जिसके अन्तर्गत विभिन्न अनिवार्य समितियों का पुनर्गठन किया जाएगा। इसके साथ विभिन्न हितधारकों को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा ताकि इस अधिनियम के अन्तर्गत आने वाली प्रक्रियाओं को गति मिल सकें।

डिजिटल प्रौद्योगिकी और शासन

142. अध्यक्ष महोदय, प्रशासनिक कार्य प्रणाली को सुगम बनाने तथा सरकारी सेवाओं का लाभ आम जन तक पहुँचाने हेतु हमारी सरकार कृत संकल्प है। आम नागरिकों की सुविधा के लिए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से प्रतिदिन औसतन 6 हज़ार Transactions होती हैं। चालू वित्त वर्ष के दौरान नवम्बर, 2024 तक 14 लाख 67 हज़ार से अधिक Transactions हो चुकी हैं। इस पोर्टल को और प्रभावी बनाने के लिए इसमें Artificial Intelligence (AI) का प्रयोग किया जाएगा।

पैरा संख्या-143 श्री एन0जी0 द्वारा जारी....

17.03.2025/1300/ए.एस.-एन.जी./1

मुख्य मंत्री...........जारी

पैरा संख्या - 142 के पश्चात.....जारी

143. हिमाचल में बार पहली "हिम परिवार परियोजना" राज्य के सभी नागरिकों का एकीकृत डेटाबेस बनाने की दिशा में हमारी सरकार की एक पहल है। अब तक इस परियोजना के तहत 19 लाख 28 हजार 270 परिवारों और 76 लाख 31 हजार 682 सदस्यों को हिम परिवार आईडी दी गई है। 2025-2026 के दौरान हिम परिवार आईडी को विभिन्न विभागीय योजनाओं के डेटाबेस में एकीकृत किया जाएगा, जिससे लाभार्थियों की पहचान सम्भव होगी और यह भी सुनिश्चित किया जा सकेगा कि कोई भी पात्र लाभार्थी किसी योजना के लाभ से वन्चित न रह जाए। इसके अतिरिक्त, "हिम एक्सेस" नामक एक State Single Sign-On (SSO) System लान्च किया गया है, जो 30 से अधिक Citizen-Centric Services को जोड़कर सेवा वितरण और अनुभव में प्रदान करेगा। यह परियोजना लाभ वितरण प्रणाली को सरल और प्रभावी बनाएगी, बार-बार दस्तावेज़ प्रस्तुत करने की आवश्यकता को कम करेगी और पात्र व्यक्तियों तक शीघ्र लाभ पहुंचाएगी। यह प्रणाली भविष्य की नीतियों के लिए सटीक डेटा भी उपलब्ध कराएगी।

144. प्रदेश में निवेश एवं उद्योग संवर्धन को बढ़ावा देने हेतु राज्य में शिमला के मैहली और कांगडा के चैतड़ू में स्थापित किए जा रहे Software Technology Park(STPI) पर कार्य पूरा किया जाएगा। इससे लगभग 500 से 650 युवाओं को नौकरियों के अवसर पैदा होंगे।

145. अध्यक्ष महोदय, उभरती प्रौद्यौगिकियों का उपयोग जहां एक ओर जन साधारण के जीवन को बेहतर बनाने में मदद करता है, वहीं दूसरी ओर इस क्षेत्र में रोजगार के नए अवसरों की भी अपार सम्भावनाएं हैं।

17.03.2025/1300/ए.एस.-एन.जी./2

अतः इस दिशा में सरकार ने "Green Himachal Vision" के लक्ष्य को 2027 तक पूरा करने के दृष्टिगत प्रदेश में Drone Technology को बढ़ावा देने का निर्णय लिया है। आगामी वित्तीय वर्ष के दौरान सरकार लोगों की सुविधा हेतु Drone Taxi सेवाएं उपलब्ध

करवाने की योजना बनाएगी जोकि विशेषकर प्रदेश के क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार की सामाग्री/कृषि उत्पाद/दवाइयां इत्यादि को पहुंचाने हेतु लाभकारी सिद्ध होगी। इसके अतिरिक्त उपरोक्त नीति के अन्तर्गत Drone Technology Intervention से कृषि एवं बागवानी के क्षेत्रों में भी आधुनिकीकरण सम्भव हो सकेगा। इसके लिए जिला हमीरपुर, मण्डी और कांगड़ा में Drone Stations स्थापित किए जाएंगे।

हाऊसिंग

146. अध्यक्ष महोदय, 2025-2026 के दौरान हिमुडा के माध्यम से 120 करोड़ रुपये की लागत से बसाल (बिलासपुर) और बिन्द्रावन (पालमपुर) में आवासीय कॉलोनियां तथा रामपुर फेज-3, रजवाड़ी (मण्डी) व धर्मपुर (सोलन) में लगभग 82 फ्लैटों और 137 रिहायशी प्लाटों को विकसित करेगी।

147. मैं 2025-2026 में हिमुडा द्वारा विकासनगर, शिमला में 250 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक विशाल व्यवसायिक परिसर के निर्माण की घोषणा करता हूं। इस व्यवसायिक परिसर को दो भागों में Plan किया जाएगा, जिसमें से एक हिस्सा सरकारी दफ्तरों व दूसरे हिस्से को Commercial Use के लिए उपयोग में लाया जाएगा।

युवा सेवाएं एवं खेल

148. अध्यक्ष महोदय, मैं खेलों को बढ़ावा देने हेतु 2025-2026 के दौरान निम्न खेल अधोसंरचना के निर्माण की घोषणा करता हूं :-

17.03.2025/1300/ए.एस.-एन.जी./3

- बिलासपुर के लूहणू में 100 बिस्तरों वाला खेल छात्रावास।
- जिला हमीरपुर के खरीड़ी में 50 बिस्तरों वाले खेल छात्रावास।

- शिमला जिला के कुटासनी में राजीव गांधी बहुद्देशीय स्टेडियम में अत्याधुनिक खेल बुनियादी ढांचे का निर्माण।
- सोलन में इण्डोर स्टेडियम के साथ-साथ रिकांगपिओ, हरोली और जयसिंहपुर में स्टेडियम का निर्माण।
- हमीरपुर तथा सुजानपुर में Synthetic Track and Field सुविधा का निर्माण ।

परिवहन

149. अध्यक्ष महोदय, सड़क यातायात प्रदेश में यातायात का मुख्य साधन है। दूर-दराज़ के इलाकों में भी बस सेवा उपलब्ध करवाने के लिए हमारी सरकार कृत संकल्प है। लोगों को स्वच्छ एवं Green Transport सेवाएं प्रदान कराने की दिशा में सरकार द्वारा डीज़ल बसों को ई-बसों में बदलने की प्रक्रिया जारी है। प्रक्रियाधीन e-Buses की खरीद के अतिरिक्त 2025-2026 में 500 और e-Buses खरीदी जाएंगी। साथ ही चार्जिंग Infrastructure की जरूरतों को पूरा करने के लिए निगम ने चार्जिंग ई-स्टेशन विकसित किए हैं तथा विभिन्न स्थानों पर इन्हें बनाने की प्रक्रिया जारी है।

150. परिवहन निगम द्वारा जनता की सुविधा के लिए शिमला में ऑनलाइन पास सुविधा शुरू कर दी है तथा इसे प्रदेश के अन्य स्थानों में शुरू करने हेतु Software तैयार कर शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

151. सरकार द्वारा शिमला शहर में यातायात की समस्या एवं कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए 1 हजार 546 करोड 40 लाख रुपये की लागत से 14.79 किलो मीटर लम्बी रोपवे की एक शहरी परिवहन परियोजना स्वीकृत की गई है, जिसका निर्माण कार्य New Development Bank के साथ समझौता ज्ञापन Sign होने के साथ ही शुरू कर दिया जाएगा तथा इसे 4 वर्षों में पूर्ण करके जनता को समर्पित कर दिया जाएगा।

पैरा संख्या-152......श्रीमती पी0बी0 द्वारा......जारी

17.03.2025/1305/ए0स0/पी0बी0/-1

152. शिमला शहर में बढ़ते यातायात की समस्या का एक कारण निजी वाहनों का बढ़ना भी है। इसी के मध्यनज़र हमारी सरकार Youth, Businesspersons, Tourists, High End Passengers etc. को ध्यान में रखकर पायलट आधार पर Luxury Vehicles को चयनित रूटों पर चलाएगी। इसके लिए सरकार द्वारा Viability Gap Funding के तहत 5 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। शिमला शहर में बसों को decongest करने के लिए Luxury buses चलाई जाएंगी।

153. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश में रेल विस्तार कार्यों को हमारी सरकार द्वारा गति दी जा रही है। प्रदेश में भानुपल्ली-बिलासपुर तथा बद्दी-चण्डीगढ़ रेल लाइनों का कार्य जोरों पर है। मैं आपके माध्यम से इस माननीय सदन को सूचित करना चाहता हूँ कि भानुपल्ली-बिलासपुर रेल लाइन की कुल लागत लगभग 10 हज़ार करोड़ रुपये है, जिसमें से भू-अधिग्रहण की लागत 1 हज़ार 200 करोड़ रुपये से अधिक है। आपको आश्चर्य होगा कि भू-अधिग्रहण के लिए भारत सरकार द्वारा केवल 52 करोड़ रुपये प्रदान किए गए हैं तथा शेष राशि लगभग । हज़ार 150 करोड़ रुपये प्रदेश सरकार द्वारा वहन किए जाने हैं। प्रदेश सरकार द्वारा अब तक कुल 848 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है।

154. 30.28 किलोमीटर लम्बी चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाईन के भूमि अधिग्रहण तथा निर्माण की कुल लागत का 50 प्रतिशत हिमाचल प्रदेश द्वारा वहन किया जा रहा है। इसकी कुल लागत लगभग 1 हज़ार 600 करोड़ रुपये है, जिसमें से भू-अधिग्रहण की लागत लगभग 600 करोड़ रुपये से अधिक है। इस रेल लाइन के लिए प्रदेश सरकार द्वारा अब तक 348 करोड़ रुपये दिए जा चुके हैं।

155. इस प्रकार भानुपल्ली-बिलासपुर-बेरी तथा चण्डीगढ़-बद्दी रेल लाइनों के निर्माण के लिए प्रदेश सरकार द्वारा लगभग 1200 करोड़ रुपये की राशि दी जा चुकी है जिसमें से 392 करोड़ रुपये की राशि तो दो सालों में कांग्रेस की वर्तमान सरकार द्वारा दी गई है।

156. अध्यक्ष महोदय, वित्त वर्ष 2025-26 के दौरान में परिवहन के क्षेत्र में निम्न कार्य करने की घोषणा करता हूंः-

- ऊना जिले के हरोली में पहला Automatic Driving Test Track स्थापित किया जाएगा।

- जलमार्गों में जैटीज़ आदि का विकास और क्रूज पर्यटन, जल क्रीड़ा गतिविधियों और जल परिवहन सेवाओं को बढ़ावा दिया जाएगा।
- 80 पेट्रोल पम्पों पर ई-वाहन चार्जिंग स्टेशन चालू किए जाएंगे और ग्रीन कॉरिडोर पर 41 स्थानों पर PPP मोड पर चार्जिंग स्टेशन स्थापित किए जाएंगे।

शहरी विकास

157. अध्यक्ष महोदय, नव गठित उन्नयित शहरी स्थानीय निकायों के विलय किए गए क्षेत्रों में बेहतर नागरिक सेवाएं जैसे सड़क, रास्ते, स्ट्रीट लाईट, सीवरेज, स्वच्छता, पार्क, पार्किंग आदि प्रदान करने के लिए राज्य सरकार वर्ष 2025-2026 के दौरान कुल 10.75 करोड़ रुपये की विकासात्मक अनुदान की राशि जारी करेगी। जिसमें नगर निगम हमीरपुर, ऊना और बद्दी के लिए प्रत्येक को एक करोड़ रुपये, नगर परिषद नदौन, बैजनाथ-पपरोला और सुन्नी के लिए 25 लाख रुपये प्रत्येक तथा नवगठित 14 नगर पंचायतों (कोटला, बंगाणा, बनीखेत, खुंडियां, नगरोटा सूरियां, झंडूता, बलद्वाड़ा, कुनिहार, धर्मपुर, सन्धोल, स्वारघाट, भोरंज, शिलाई व बड़सर) के लिए 50 लाख रुपये प्रत्येक के रूप में प्रदान की जाएगी। मैं जनता को यह भी अश्वासन दिलाना चाहता हूँ कि नव गठित शहरी निकायों में शामिल किए गए ग्रामीण क्षेत्रों में 3 वर्षों तक Property Tax में छूट प्रदान की गई है तथा पानी के रेट भी पहले के समान ही रहेंगे।

158. सरकार द्वारा शहरी स्थानीय निकायों के माध्यम से लगभग 44 सेवाएं प्रदान की जा रही है जिन्हें State Project Monitoring Unit (SPMU) के माध्यम से चरणबद्ध तरीके से UPYOG प्लेटफार्म पर लाया जाएगा।

159. माननीय अध्यक्ष महोदय, मेरी सरकार ने शहरीकरण का बड़े पैमाने पर विस्तार किया है क्योंकि यह राज्य के समग्र विकास के लिए महत्वपूर्ण है। राष्ट्रीय स्तर पर भी Tier-1 शहरों को Decongest करके, Tier-II और Tier-III शहरों के विकास पर बल दिया जा रहा है। अतः इस सन्दर्भ में हमारी सरकार वर्तमान विकास योजनाओं का पुनर्निरीक्षण तथा महत्वपूर्ण शहरी/पर्यटक क्षेत्रों में "**Business District Zone**" की स्थापना पर विचार करेगी।

160 श्री ए0पी0 द्वारा जारी...

17.03.2025/1310/एपी/एएस/1

160. सरकार प्रदेश के शहरी क्षेत्र के छोटे फल-सब्जी विक्रेताओं, चाय दुकानदारों, नाई की दुकानों, पान की दुकानों, जूता मुरम्मत की दुकानों, चाट, टिक्की, चना इत्यादि की दुकानों और खोमचे वालों, छोटे ढाबा मालिकों और अन्य छोटे परचून दुकानदारों के लिए "**मुख्य मन्त्री लघु दुकानदार कल्याण योजना**" में लचीलापन लाते हुए इसका विस्तार करेगी। इस योजना के तहत Distressed छोटे दुकानदारों, जो कर्जे में दबे हुए हैं, वैसे इसमें डिस्ट्रैस्ड लिखा है, मैं इसका हिंदी अनुवाद कर रहा हूं, जिनका Annual Turnover 10 लाख रुपये से कम है, को बैंक के माध्यम से 1 लाख रुपये तक के One Time Settlement(OTS) की सुविधा दी जाएगी व Loan पर लगने वाले Interest को सरकार वहन करेगी। इस योजना से छोटे दुकानदार, विक्रेता अपनी व्यवसायिक गतिविधियों का विस्तार कर सकेंगे। यह योजना न केवल इन विक्रेताओं की आर्थिक स्थिति में सुधार करेगी अपितु राज्य के लघु व्यापारियों को सशक्त बनाने और अर्थव्यवस्था को मजबूत करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। इस योजना के लिए 100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

अध्यक्ष महोदय, पिछले दिनों मैं धर्मशाला गया और मैं वहां पर एक चाय कि दुकान में बैठा। इस योजना का आइडिया हमें कहां से आया, उस समय मेरे साथ संजय रत्न जी, चौधरी चन्द्र कुमार जी भी थे, हम कई लोग थे। उस समय एक बेटी जो 10+2 पढ़ी थी वह हमें दूर से देख रही थी । मैंने उसे बुलाया और पूछा कि आप क्या देख रहे हो? वह बोलने लगी कि मैं देख रही हूं कि मुख्य मंत्री जी कौन से हैं? फिर मैंने उससे पूछा कि आप क्या करते हो? वह बोली कि मैं सब्जियों की दुकान लगाती हूं। सुबह 4.00 बजे उठती हूं। मेरा एक भाई और बहन हैं और हम अनाथ हैं। हमारे मां-बाप हमें छोड़कर चले गए हैं। मैंने पूछा कि आपने हमारी योजना का लाभ क्यों नहीं उठाया? उसने कहा कि मैं 28 साल की

हो चुकी हूं। उसने बताया कि मैंने 1 लाख रुपये का लोन लिया। वह ब्याज में रेगुलर चलते-चलते बढ़ जाता है। उस समय हमारे मन यह विचार आया कि जो भी गरीब है, उसके लिए One Time Settlement Policy लाई जाएगी और उन सभी विक्रेताओं का जो ब्याज होगा, हिमाचल प्रदेश की सरकार अपनी सम्पदा का, जो हमारी सम्पदा है, यह सारी जो

17.03.2025/1310/एपी/एएस/2

बजट या सम्पदा है, उस हिस्से को उन परिवारों को भी देगी, जिन परिवारों को इस हिस्से से वंचित रखा गया है। इससे काफी लोगों को राहत मिलेगी।

161. मैं स्थानीय नगर निकायों के प्रतिनिधियों को प्रतिमाह दिये जाने वाले मानदेय को निम्न प्रकार से बढ़ाने की सहर्ष घोषणा करता हूंः-

महापौर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 25,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-महापौर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 19,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

काउंसलर, नगर निगम को 1,000 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,400 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

अध्यक्ष, नगर परिषद को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 10,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उपाध्यक्ष, नगर परिषद को 500 रुपये बढ़ौतरी के साथ 8,900 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

पार्षद, नगर परिषद को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रमिमाह मानदेय मिलेगा।

प्रधान, नगर पंचायत को 600 रुपये बढ़ौतरी के साथ 9,000 हज़ार रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

उप-प्रधान, नगर पंचायत को 400 रुपये बढ़ौतरी के साथ 7,000 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

17.03.2025/1310/एपी/एएस/3

सदस्य, नगर पंचायत को 300 रुपये बढ़ौतरी के साथ 4,500 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

शहरी विकास के क्षेत्र में कुल 656 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

162. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार द्वारा प्रदेश में लोगों को विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत स्वच्छ पेयजल की सुविधा प्रदान की जा रही है। चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश के ठण्डे क्षेत्रों में Antifreeze और शीतकालीन जलापूर्ति योजनाओं के तहत जिला लाहौल स्पिति के लिए 27 करोड़ रुपये की लागत से 20 करोड़ रुपये Water Supply Scheme और किन्नौर जिले में 72 करोड़ रुपये की लागत से 6 Water Supply Schemes का कार्य आरम्भ किया जाएगा। इस वर्ष नादौन, भोरंज, अमलेहड़ और हरोली में 4 Water Supply Scheme और बद्दी के लिए एक Sewerage Scheme का निर्माण कार्य पूरा किया जाएगा।

श्री ए0टी0 द्वारा जारी ......

17.03.2025/1315/AT/ डी0सी0/1

163. 298 करोड़ 87 लाख की अनुमानित लागत से 17 नगरों (मण्डी, ठियोग, राजगढ़, चम्बा, हमीरपुर, सुन्नी, रामपुर, डलहौजी, अम्ब, भुन्तर, नाहन, ज्वाली, बैजनाथ, अर्की, निरमण्ड, पालमपुर और जोगिन्द्रनगर) में पेयजल आपूर्ति की जा रही है। इनमें से 11 नगरों में कार्य प्रगति पर है तथा शेष नगरों में कार्य वित्त वर्ष 2025-2026 के दौरान किया जाएगा। इसके अतिरिक्त 2025-2026 में ही 9 अन्य नगरों क्रमशः भुन्तर, नाहन, ज्वाली, अर्की, निरमण्ड, जोगिन्द्रनगर, शाहपुर, भटियात और करसोग में कुल 167 करोड़ रूपये की लागत से पेयजल योजनाओं का निर्माण शुरू किया जाएगा।

164. शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में 24X7 पेयजल आपूर्ति प्रणाली के तहत सरकार द्वारा प्रत्येक जिले में एक क्षेत्र को चिन्हित (कुल 12) किया गया। इनमें से विभिन्न परियोजनाओं के अन्तर्गत 5 क्षेत्रों कम्रशः GWSS रामपुर (वार्ड न० 6 और 7), GWSS चम्बा (वार्ड न० 10), LWSS नालागढ़ (वार्ड न० 7), LWSS घुमारवीं (वार्ड न0 2 और 5), व LWSS नादौन नगर में कार्य प्रगति पर है तथा शेष क्षेत्रों में शीघ्र ही कार्य आरम्भ कर दिया जाएगा।

165. प्रदेश में 58 स्थानीय शहरी निकायों में जलशक्ति विभाग द्वारा जलापूर्ति की जाती है। इनमें से 23 नगरों में उन्नयन और सुधार कार्य चल रहे हैं। 9 नगरों की परियोजनाओं पर कार्य वित्तीय वर्ष 2025-2026 में शुरू कर दिया जाएगा। इसके अतिरिक्त 4 नगरों (नेरवा, चिड़गांव, कण्डाघाट और टाहलीवाल) का उन्नयन प्रस्ताव तैयार किया जा रहा है।

166. हमारी सरकार NDB के द्वारा वित्त पोषित हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन परियोजना के तहत 7 सौ 45 करोड़ की लागत से 8 जिलों में ग्रामीण क्षेत्रों में 20 हज़ार 663 घरों तक बेहतर आपूर्ति सुनिश्चित करेगी। इन सभी योजनाओं का कार्य 2025-2026 के अन्त तक पूरा किया जाएगा।

167. हिमाचल प्रदेश ग्रामीण पेयजल उन्नयन एवं आजीविका परियोजना के तहत लगभग एक हजार 62 करोड़ से अधिक की लागत से 10 जिलों की 2471 बस्तियों में लगाए जा

17.03.2025/1315/AT/ डी0सी0/2

रहे 79 हजार 282 Functional House Hold Tap Connection (FHTCs) का 43 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो चुका है तथा शेष कार्य शीघ्र पूर्ण कर लिया जाएगा।

168. हिमाचल प्रदेश में जल आपूर्ति की गुणवत्ता में सुधार लाने के उद्देश्य से मैं "मुख्य मंत्री स्वच्छ जल शोधन योजना‛ की घोषणा करता हूं। योजना में नवीनतम तकनीकों जैसे Ozonation, UV filtration, RO और नैनो फिल्ट्रेशन इत्यादि का उपयोग कर जल शोधन कर स्वच्छ जल हिमाचल की जनता को उपलब्ध करवाया जाएगा। घरेलू और व्यावसायिक जल आपूर्ति योजनाओं का भी उन्नयन किया जाएगा ताकि उच्च गुणवत्ता वाला जल लोगों तक पहुंच सके। इस योजना के माध्यम से प्रदेश में स्वच्छ और सुरक्षित पेयजल की

उपलब्धता बढ़ेगी और जल जनित बीमारियों की रोकथाम में और मदद मिलेगी। इस योजना के अन्तर्गत 80 करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है।

169. हमारी सरकार द्वारा लोगों को स्वच्छ पेयजल प्रदान करने के लक्ष्य की दिशा में अगला कदम बढ़ाते हुए जिला कांगड़ा के ज्वालामुखी, जसवां, प्रागपुर व देहरा में आगामी वित्त वर्ष के दौरान 43 करोड़ रूपये की लागत से Drinking Water Treatment Plants लगाए जाएंगे।

170. प्रदेश के 10 जिलों में (किन्नौर और लाहौल-स्पिति को छोड़कर) 291 चयनित योजनाओं में सेन्सर आधारित Real Time Monitoring System (Internet of Things) स्थापित की जा रही है। जिसके द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता, मात्रा की नियमित निगरानी की जाएगी।

171. हमारी सरकार द्वारा पीने के पानी की गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए राज्य स्तर पर एक और सभी जिला स्तर पर 14 Bacteriological मापदण्डों के लिए National Accreditation Board for Testing and Calibration Laboratories (NABL) से मान्यता प्राप्त जल परीक्षण प्रयोगशालाएं स्थापित कर की जाएंगी। इसके अतिरिक्त विभिन्न जल आपूर्ति, सिंचाई और सीवरेज योजनाओं में Green Energy का प्रयोग करने के लिए सौर पेनलों की स्थापना हिम ऊर्जा के माध्यम से की जानी प्रस्तावित है।

17.03.2025/1315/AT/ डी0सी0/3

172. प्रदेश में 6 नगरों (भोटा, सन्तोखगढ़, तलाई, बैजनाथ-पपरोला, नेरचौक और बंजार) जहां सीवरेज की सुविधा उपलब्ध नही है, उनमें सीवरेज योजनाओं के अन्तर्गत कार्य प्रगति पर है। 5 नगरों (नेरवा, चौपाल, राजगढ़, शाहपुर और बिलासपुर) के लिए सीवरेज योजनाओं का कार्य वर्ष 2025-2026 में आरम्भ कर दिया जाएगा। इस सुविधा से वंचित शेष 9 नगरों हेतु भी प्रस्ताव तैयार किए जा रहे हैं।

173. ग्रामीण क्षेत्रों में सरकार ने वर्तमान में 41 सीवरेज योजनाओं को विभिन्न कार्यक्रमों के तहत स्वीकृत किया है, जिसमें से कांगड़ा, मण्डी, चम्बा और किन्नौर जिलों के 14 कस्बों में सीवरेज योजनाओं पर कार्य वर्ष 2025-2026 में शुरू किया जाएगा।

स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण

174. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार राज्य के प्रत्येक नागरिक को बेहतर चिकित्सा सुविधाएं उपलब्ध करवाने के लिए समूचे प्रदेश में चिकित्सा संस्थान तथा मैडिकल कॉलेजों में आधुनिक विशेषज्ञ सेवाएं प्रदान करने हेतु प्रतिबद्ध है। महोदय, मैने पहले बजट में प्रत्येक विधान सभा क्षेत्र में एक स्वास्थ्य संस्थान को "आदर्श स्वास्थ्य संस्थान" के रूप में विकसित करने घोषणा की थी। हमारी सरकार द्वारा व्यवस्था परिवर्तन के फलस्वरूप स्वास्थ्य के क्षेत्र में गत दो वर्षों के दौरान किए गए कार्यों के सुखद परिणाम सामने आने लगे हैं। 2025-2026 के दौरान सरकार द्वारा इन स्वास्थ्य संस्थानों में निम्न सुविधाएं प्रदान की जाएंगीः-

श्रीमती एम0डी0 द्वारा जारी...

13.03.2025/1320/md/HK/1

मुख्य मंत्री.......जारी

- 69 संस्थानों में से 20 संस्थानों में डॉयलेसिस सेवाएं प्रदान की जा रही हैं तथा शेष बचे संस्थानों में लगभग 45 करोड़ की लागत से 49 यूनिट हस्थापित किए जाएंगे।
- आगामी वित्त वर्ष में 11 संस्थानों घवांडल, चुवाड़ी, भोरंज, नादौन, तयारा, जयसिंहपुर, पधर, धर्मपुर, जुन्गा, हरोली व अम्ब में ब्लड स्टोरेज यूनिट्स स्थापित की जाएंगी।
- बीमार नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए हमीरपुर, बिलासपुर, चम्बा, कांगड़ा, कुल्लू, मण्डी, शिमला, सिरमौर और ऊना जिलों में 17 Newborn Stabilization Units स्थापित की जाएंगी।

175. हमारी सरकार द्वारा लोगों को अत्याधुनिक Medical Technology से लैस AIIMS-Delhi के स्तर की सुविधाएं उपलब्ध करने के उद्देश्य से 45 करोड़ 50 लाख रुपये की लागत से AIMSS Chamiana, Shimla व टाण्डा मैडिकल कॉलेज, कांगड़ा में Robotic Surgery स्थापित करने की प्रक्रिया जल्द ही पूर्ण कर दी जाएगी। IGMC Shimla में 20 करोड़ 73 लाख 12 हज़ार रुपये की लागत से Positron Emission Tomography (PET) Scan की सुविधाएं अगले तीन महीनों में उपलब्ध करवाई जाएगी। इसके अतिरिक्त लगभग 100 करोड़ रुपये की लागत से आवश्यक Infrastructure सहित MRI की अत्याधुनिक मशीनें IGMC Shimla, AIMSS Chamiana, Shimla, Govt. Medical College Hamirpur तथा Govt Medical College Ner Chowk में स्थापित की जाएंगी।

अध्यक्ष महोदय, शिमला में हमारा प्रीमियम इंस्टीच्यूट है और यहां पर 19 साल पुरानी एम0आर0आई0 की मशीन लगी हुई है। इसलिए हम टैक्नोलॉजी पर भी ज्यादा खर्च कर रहे हैं।

176. अध्यक्ष महोदय, मैं इस माननीय सदन के माध्यम से सभी को सूचित करना चाहता हूं कि प्रदेश के सभी "मैडिकल कॉलेजों" एवं "आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों" में विश्व स्तरीय उपचार उपलब्ध करवाने हेतु बहुत जल्द और अधिक उच्च गुणवत्ता वाले अत्याधुनिक उपकरण उपलब्ध करवाए जाएंगे, जिसके लिए जापान की इन्टरनेशनल को-ऑपरेशन एजेन्सी (JICA) के माध्यम से संसाधनों की उपलब्धता हेतु 1 हजार 700 करोड़ रुपये सुनिश्चित किए जा रहे हैं।

177. मेडिकल कॉलेज हमीरपुर और राजकीय मेडिकल कॉलेज नेर चौक (मण्डी) में हृदय रोगियों की सुविधा के लिए Cath. Lab की स्थापना की जाएगी।

178. प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं को मजबूत करने के हमारे प्रयासों के तहत, 10 नए Health and Wellness Centres की स्थापना की जाएगी। ये केंद्र, निजी क्षेत्र के सहयोग से स्थापित किए जाएंगे।

179. अध्यक्ष महोदय, प्रदेश के Medical Colleges तथा AIMSS चमियाना में PG को Senior Resident/Tutor Specialist को वर्तमान में वज़ीफे के रूप में प्रथम, द्वितीय एवं

तृतीय वर्ष की पढ़ाई हेतु प्रदान की जा रही राशि क्रमशः 60 हज़ार, 62 हज़ार व 65 हज़ार को बढ़ाकर एक लाख रुपये करने की घोषणा करता हूं तथा साथ ही DNB-Super Specialist & Sr. Residents-Super Specialist (D.M./M.Ch.) के वज़ीफे की राशि को भी वर्तमान दर क्रमशः 60 हज़ार, 62 हज़ार व 65 हजार से बढ़ाकर एक लाख 30 हजार रुपये करने की घोषणा करता हूं। **अध्यक्ष महोदय, यह घोषणा इसलिए कर रहा हूं ताकि कोई डॉक्टर प्रदेश को छोड़ कर न जाए।**

180. राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को और सुदृढ़ करने व मरीजों की देख-भाल हेतु "रोगी मित्र योजना" के अन्तर्गत प्रदेश के विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों में एक हज़ार के करीब रोगी मित्र नियुक्त किए जाएंगे। इन रोगी मित्रों को 15 हज़ार रुपये मासिक मानदेय देय होगा, जिस पर राज्य सरकार 18 करोड़ रुपये व्यय करेगी।

अध्यक्ष महोदय, हम अपने हैल्थ सिस्टम को सुधार रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में कुछ सुधार हो चुका है तथा अभी और सुधार होना है। हैल्थ सैक्टर में अभी बहुत कम लगभग 20 प्रतिशत सुधार हुआ है और शिक्षा के क्षेत्र में लगभग 50 प्रतिशत सुधार हुआ है। हम हैल्थ सिस्टम को भी ठीक करेंगे।

श्रीमती के0एस0 द्वारा जारी

17.03.2025/1325/केएस/एचके/1

181. मुझे यह घोषणा करते हुए अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश में आउटसोर्स पर नियुक्त Operation Theater Assistant का मासिक मानदेय 7 हजार 1 सौ अस्सी रूपये की वृद्धि के साथ 17 हजार 820 रूपये से तथा Radiographer का मासिक मानदेय 11 हजार 9 सौ रूपये की वृद्धि के साथ 13 हजार 100 रूपये से बढ़ाकर 25 हजार रूपये किया जाएगा। अभी किसी को 11 हजार मिल रहा है, किसी को 13 हजार मिल रहा है।

182. हमारी सरकार स्वास्थ्य सेवाओं का जनता के घर-द्वार से ही लाभ लेने व अस्पतालों की लम्बी कतारों से निजात पाने के लिए सुगम स्वास्थ्य नाम की नई App शुरू करेगी प्रदेश के 6 मैडिकल कॉलेज अस्पतालों, AIMSS चम्याणा, कमला नेहरू अस्पताल, 9

जिला अस्पतालों तथा 36 जिला अस्पतालों में उपचार हेतु हर प्रदेशवासी घर से ही ऑन लाईन Appointment ले सकता है। लोग बेचारे पर्ची कटवाने के लिए बैठे रहते हैं।

183. अध्यक्ष महोदय, जैसा की आपको स्मरण होगा कि मैंने वर्ष 2023-2024 के बजट भाषण में घोषणा की थी कि सरकार टाइप-1 डायबिटीज़ से पीड़ित गर्भवती महिलाओं और बच्चों के लिए मुफ्त इन्सुलिन पम्प उपलब्ध करवाएगी। इसी दिशा में एक और कदम बढ़ाते हुए मैं घोषणा करता हूं कि आगामी वित्त वर्ष से यह सुविधा अब 27 वर्ष तक के लड़के और लड़कियों के लिए भी उपलब्ध करवाई जाएगी।

184. सरकार द्वारा आगामी वित्त वर्ष के दौरान Palliative Care (राष्ट्रीय प्रशामक स्वास्थ्य) देखभाल कार्यक्रम के अन्तर्गत हिमाचल सरकार गम्भीर बीमारियों से ग्रसित लगभग 12 हजार रोगियों के लिए पैलिएटिव केयर सेवाएं प्रदेश में चरणबद्ध तरीके से लागू करने के साथ-साथ सभी आदर्श स्वास्थ्य संस्थानों को पैलिएटिव केयर (Palliative Care) हब के रूप में विकसित किया जाएगा। जिसमें स्वास्थ्य कर्मी मरीजों के घर जाकर उपचार करेंगे और परिवार के सदस्यों को देखभाल का प्रशिक्षण देंगे।

185. वरिष्ठ नागरिकों की स्वास्थ्य सेवाओं को सुगम बनाने के लिए "मुख्यमन्त्री वृद्धजन देखभाल योजना" नामक नई योजना लाई जाएगी। इस योजना के तहत स्वास्थ्य और पैरामेडिकल स्टाफ मोबाइल स्वास्थ्य वैन के माध्यम से 70 वर्ष या इससे अधिक आयु के लोगों के घर जाकर स्वास्थ्य परीक्षण करेगें, जिससे उनकी स्वास्थ्य

17.03.2025/1325/केएस/एचके/2

सम्बन्धी आवश्यकताओं को प्राथमिकता के आधार पर पूरा किया जा सकेगा। यह पहल सरकार की वृद्धजन के प्रति संवेदनशीलता और आदर को दर्शाता है।

186. बच्चों में कुपोषण की समस्या को देखते हुए हमीरपुर जिले में आई०आई०टी० मुम्बई के समन्वय से पायलट आधार पर 6 माह से अधिक आयु के बच्चों के स्तनपान की इम्प्रोवाइज (Improvise) तकनीक और पूरक आहार पर अध्ययन किया जाएगा।

187. कठिन भौगोलिक और जलवायु परिस्थितियों के कारण दुर्गम और अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाएं सुचारू रूप से उपलब्ध करवाने के लिए अतिरिक्त 290 आशा कार्यकर्ताओं का चयन किया जाएगा।

188. प्रदेश में स्वास्थ्य विभाग की नीतियों और कार्यक्रमों की योजना, कार्यान्वयन, निगरानी और मूल्यांकन को आसान बनाने के लिए "राज्य स्वास्थ्य प्रणाली संसाधन केंद्र" (SHSRC) स्थापित किया जाएगा। यह केंद्र स्वास्थ्य क्षेत्र में शोध, स्वास्थ्य कर्मियों की क्षमता निर्माण, और गैर सरकारी संगठनों, शैक्षणिक संस्थानों और सामुदायिक संगठनों के साथ साझेदारी को बढ़ावा देगा।

189. प्रदेश में नवजात शिशुओं के बेहतर स्वास्थ्य देखभाल के लिए, कमला नेहरू अस्पताल शिमला और मेडिकल कॉलेज, नेरचौक, मण्डी में Command Centre स्थापित किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त, प्रदेश के अन्य सभी Sick Newborn Care Units को इन Command Centre से Tele-Consultation के माध्यम से जोड़ा जाएगा। इससे बीमार नवजात बच्चों की देखभाल और अधिक प्रभावी ढंग से हो सकेगी।

190. प्रदेश में एम्बुलेंस सेवा को और अधिक सुदृढ़ बनाने के लिए 25 Advanced Life Support एम्बुलेंस की खरीद की जाएगी।

श्रीमती अ0व0 द्वारा जारी---

17.03.2025/1330/av/yk/1

मुख्य मंत्री क्रमागत----------

191. हम सभी, राज्य में बढ़ते नशीली दवाओं के दुरुपयोग के मामलों को लेकर बहुत चिंतित हैं। मेरी सरकार ने इस समस्या के आपूर्ति और मांग पक्ष, दोनों पर गंभीरता से काम किया है। मेरा दृढ़ विश्वास है कि हमें अपने बच्चों को अपराधी न मान कर पीड़ित मानना चाहिए। हमें ऐसे बच्चों के पुनर्वास पर अधिक जोर देने की आवश्यकता है। अतः इस सन्दर्भ में मैं निम्न घोषणाएं करता हूं :-

- सरकार नशीली दवाओं के दुरुपयोग की रोकथाम हेतु Drug Dependence Prevention, De-addiction, and Rehabilitation Board का गठन मुख्य मन्त्री की अध्यक्षता में करेगी।
- सरकार PGIMER चंडीगढ़ और AIIMS नई दिल्ली के परामर्श से नशीली दवाओं के दुरुपयोग और पुनर्वास हेतु एक Action Plan विकसित करेगी।
- Action Plan का महत्वपूर्ण हिस्सा एक राज्य-व्यापी जागरूकता और समुदायिक लामबंदी अभियान होगा, जिसमें पंचायतों, धार्मिक/सांस्कृतिक संगठनों, युवा क्लबों, एन0सी0सी0, एन0एस0एस0, शिक्षकों, महिलाओं के समूहों और NGO सहित सभी हितधारकों को शामिल किया जाएगा। इसमें स्थानीय चैंपियन (खिलाड़ी, प्रभावशाली व्यक्ति, युवा आइकन और अन्य) शामिल किए जाएंगे। सामुदायिक रेडियो, स्थानीय प्रेस, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, सोशल मीडिया और Public Events का भी इस्तेमाल किया जाएगा।
- मैडिकल कॉलेज, टाण्डा में एक Drug De-addiction and Rehabilitation नोडल केन्द्र स्थापित किया जाएगा तथा चरणबद्ध तरीके से इन केंद्रों का राज्यव्यापी विस्तारीकरण किया जाएगा।
- सिरमौर जिला के कोटला बीड़ में एक Drug De addiction and Rehabilitation केंद्र चालू किया जाएगा।
- क्षेत्रीय/जिला/मेडिकल कॉलेजों/अस्पतालों में आवश्यकता के अनुसार डी-एडिक्शन बैड्स की संख्या बढ़ाई जाएगी।

17.03.2025/1330/av/yk/2

- डी-एडिक्शन देखभाल में विशेषज्ञता की कमी को पूरा करने के लिए डॉक्टरों, नर्सों, सी0एच0ओ0 और अन्य प्रदाताओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा।

- Psychiatrist, Clinical Psychologists, और Psychiatric Social Worker के पदों को भरने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे। इसके अतिरिक्त मनोचिकित्सा में PG सीटों को बढ़ाने के लिए कदम उठाए जाएंगे।
- नीति आयोग उन जिलों में नशा उपचार सुविधाओं (ATFs) के लिए योजनाएं तैयार करने में सरकार की सहायता करेगा जहां ऐसी सुविधाएं नहीं हैं।
- सरकार नीति आयोग के सहयोग से प्रदेश में "स्कूल स्वास्थ्य कार्यक्रम" के तहत यह सुनिश्चित करेगी कि हमारे प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों (PHCs) के डॉक्टर और पैरामैडिकल स्टॉफ नजदीकी स्कूलों में नियमित रूप से छात्रों की स्वास्थ्य जांच के साथ-साथ Counselling-cum-Awareness Session भी आयोजित करेंगे जोकि छात्रों को स्वास्थ्य के प्रति जागरूक करेगा। इस योजना के प्रभावी कार्यान्वयन के लिए उपमण्डल स्तर पर एक समिति का गठन किया जाएगा, जिसकी अध्यक्षता सम्बन्धित उपमण्डल अधिकारी करेंगे।

192. अध्यक्ष महोदय, हम यह नहीं समझ पाते हैं, लेकिन एक तथ्य यह भी है कि Internet के इस युग में बड़ी संख्या में जनसंख्या को सही और निरन्तर नींद नहीं मिलती है। यदि इस समस्या का समय पर निदान और उपचार नहीं किया गया तो यह अन्य विभिन्न बीमारियों को जन्म देता है। अतः एक उद्भव और गंभीर परिणामों वाले महत्वपूर्ण विकार Obstructive Sleep Apnea (नींद में रुकावट) में विशेषज्ञता विकसित करने के लिए सरकार PGIMER चंडीगढ़ में राज्य के मेडिकल कालेजों के चयनित संकाय को प्रशिक्षण प्रदान करेगा।

193. देश के प्रमुख स्वास्थ्य संस्थानों की तरह, राज्य के स्वास्थ्य संस्थान भी मरीजों की भारी भीड़ को प्रबंधित करने में संघर्ष कर रहे हैं। राज्य सरकार एक कार्यक्रम शुरू करेगी, जिसमें स्थानीय शिक्षण संस्थानों के एन0एस0एस0 (राष्ट्रीय सेवा योजना) के

17.03.2025/1330/av/yk/3

छात्रों को चरणबद्ध तरीके से स्वैच्छिक सेवाएं प्रदान करने के लिए शामिल किया जाएगा। इस पहल का उद्देश्य बेहतर अस्पताल प्रबंधन, मरीजों के लिए एक सुगम अनुभव और छात्रों व युवाओं में करूणा और स्वैच्छिक सेवा की भावना का विकास सुनिश्चित करना है। स्वास्थ्य के क्षेत्र में कुल 3,481 करोड़ रुपये प्रस्तावित हैं।

ऊर्जा

194. सरकार का लक्ष्य वर्ष 2026 तक देश का पहला हरित राज्य बनाना है। HPPCL के माध्यम से लगभग 626 मेगावाट क्षमता की सौर परियोजनाएं विकास के विभिन्न चरणों में है।

- 200 मेगावाट का एक बड़ा सोलर प्रोजैक्ट कांगड़ा डमटाल में लगाया जाएगा जिसे एक वर्ष में पूरा करने का लक्ष्य रखा है। इससे सालाना 320 Million Units बिजली का उत्पादन होगा और प्रति वर्ष लगभग 150 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।
- "ग्रीन पंचायत योजना" के तहत 100 पंचायतों में 500-500 किलोवॉट के सोलर प्रोजैक्ट लगाए जाएंगे।

195. शोंगटोंग जल विद्युत परियोजना (450 मेगावाट) पिछले 15 वर्षों से अधिक समय से लम्बित है। सरकार ने कार्य को गति दी है। अब इस परियोजना के दिसम्बर, 2026 तक चालू करने का लक्ष्य है। इस परियोजना से सालाना लगभग एक हज़ार करोड़ रूपये का राजस्व प्राप्त होगा।

टी सी द्वारा जारी

17.03.2025/1335/टी0सी0वी0/वाई0के0-1

मुख्य मंत्री .... जारी

196. एकीकृत काशंग जल विद्युत परियोजना (130 मेगावाट) की प्रगति पर भी विशेष ध्यान दिया जा रहा है तथा जून, 2026 तक परियोजना के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा गया है। इस परियोजना से प्रतिवर्ष 350 करोड़ रुपये का राजस्व प्राप्त होगा।

197. पम्प भंडारण परियोजनाओं से बिजली क्षेत्र के विकास की गति में वृद्धि होगी। प्रारम्भ में HPPCL को रेणुका जी (1630 मेगावाट) और थाना-प्लाउन(150 मेगावाट) परियोजनाएं आबंटित की गई है। ये परियोजनाएं एक ओर हाइड्रो बैटरी की तरह काम करेगी और ग्रिड स्टेबिलिटी को बढ़ाएगी जिससे अतिरिक्त राजस्व अर्जित होगा।

198. इसके अलावा पम्प स्टोरेज प्रोजैक्ट (PSP) की स्थापना के लिए बी0बी0एम0बी (13000 मेगावाट) एस0जे0वी0एन0ए0 (2500 मेगावाट), एन0टी0पी0सी0 (2400 मेगावाट) और निजी उत्पादकों (2000 मेगावाट) से भी प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। इन प्रस्तावों पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा।

199. प्रदेश सरकार विद्युत उत्पादन के क्षेत्र में पुनः तेजी लाने के लिए प्रयासरत है। हमने इस क्षेत्र की समस्याओं का अध्ययन करने और उनके समाधान का सुझाव देने के लिए कैबिनेट सब-कमेटी का गठन किया है, जिसमें अपनी अनुशंसा सरकार को सौंप दी है। इन्हें ध्यान में रखते हुए हम ऊर्जा क्षेत्र को पुनर्जीवित करेंगे।

200. हमने प्रदेश की सरकार ओर से केंद्र सरकार और राज्य सरकारों के उपक्रमों को ऊर्जा क्षेत्र में निवेश का आमंत्रण दिया है। तेलंगाना सरकार ने प्रदेश में हाइड्रो प्रोजेक्ट्स में निवेश में रुचि दिखाई है। शीघ्र ही आपसी चर्चा के बाद हम तेलंगाना सरकार की जेनरेशन कंपनी के साथ इस दिशा में आगे बढ़ेंगे और एम0ओ0यू0 के माध्यम से चिन्हित परियोजनाओं का कार्य आरंभ करेंगे। हम अगले वर्ष में ऊर्जा क्षेत्र में निजी निवेश को और

भी बनाएंगे और ग्रीन हिमाचल के लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आगे बढ़ेंगे। बिजली 12, 18, 30, और 40 की वर्ष बाद प्रोजेक्ट्स को वापस करने की हमारी

17.03.2025/1335/टी0सी0वी0/वाई0के0-2

जो पॉलिसी है उसके तहत तेलंगाना गवर्नमेंट ने रुचि दिखाई है और जल्दी ही एम0ओ0यू0 होने वाला है।

201. बिजली ट्रांसमिशन के क्षेत्र में कांगू (जिला मंडी) और टालीवाल (जिला ऊना) में 220 के0वी0 सब-स्टेशन में कार्य को पूर्ण करने का इस वर्ष लक्ष्य रखा गया। इनकी कुल लागत 103 करोड1 रुपये है। इसके अलावा 82 करोड़ रुपये के निवेश से 2025-26 में धर्मपुर (जिला मंडी) और बरसैनी (जिला कुल्लू) में 132 के0वी0 के दो सब-स्टेशन के कार्य को पूर्ण करने का लक्ष्य रखा है। सरकार की इस योजना से 426 एम0बी0ए0 तक परिवर्तन क्षमता में वृद्धि होगी। सरकार वर्ष 2025-26 के दौरान 78 सर्किट किलोमीटर ई0एच0बी0 ट्रांसमिशन लाइन का कार्य भी समाप्त करेगी जिसमें 132 के0वी0 बरसैनी-चरोर लाइन (जिला कुल्लू) की 76 सर्किट किलोमीटर और 400 के0वी0 कुटेहर-लिलो (जिला चंबा) दो सर्किट किलोमीटर है। इसके अतिरिक्त जिला ऊना में 220 एम0वी0ए0 220/132 के0वी0 सब-स्टेशन जिनकी अनुमानित लागत 88.22 करोड़ है, का कार्य आरम्भ किया जाएगा।

202. उपभोक्ताओं को क्वालिटी पावर सप्लाई सुनिश्चित करने के उद्देश्य से चरणबद्ध तरीके से आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर विकसित किया जाएगा। इसकी शुरुआत करते हुए कांगड़ा जिला के गनोग (नूरपुर), करला कोटला (देहरा) मझीण (ज्वालामुखी) मौकी (इंदौर) समलोटी (नगरोटा बागवां) और थेर (ज्वालामुखी) में आगामी वित्त वर्ष में 33/11 के0वी0 के 6 सब-स्टेशन बनाए जाएंगे।

ऊर्जा के क्षेत्र में कुल 905 करोड़ रुपया प्रस्तावित है।

भाषा एवं संस्कृति

203. वित्तीय वर्ष 2025-26 में प्रदेश के पारंपरिक वास्तुशिल्प एवं व्यंजनों को बढ़ावा देने के वैंटनी कैसल, शिमला के परिसर में दिल्ली हाट की तर्ज पर हिमाचल प्रदेश राज्य ग्रामीण आजीविका मिशन के अंतर्गत स्वयं सहायता समूह/शिल्पकारों हेतु स्थान स्थापित किया जाएंगे।

204. प्रदेश सरकार द्वारा राज्य के छोटे मंदिरों को वार्षिक आधार पर धूप-बत्ती के लिए अनुदान दिया जाता रहा है। आगामी वित्त वर्ष के दौरान सरकार राज्य समर्थित इन मंदिरों को वर्तमान में दी जा रही अनुदान की राशि को दुगना करेगी।

205. कुल्लू के नगर में अंतरराष्ट्रीय रौरिक मेमोरियल ट्रस्ट है। यह पर्यटन का मुख्य केंद्र है और साथ ही यह भारत और रूस की मैत्री का भी प्रतीक है। इस पूरे क्षेत्र को पूरे क्षेत्र को पर्यटन की दृष्टि से विकसित किया जाएगा और इसका मास्टर प्लान बनाकर अंतरराष्ट्रीय संस्थाओं को वित्त-पोषण के लिए भेजा जाएगा। मैं इस ट्रस्ट के बेहतर प्रबंधन के लिए अगले वित्तीय वर्ष से 15 लाख रुपये का वार्षिक अनुदान दिए जाने की घोषणा करता हूं।

सैनिक कल्याण

206. गत वर्ष की भांति हमारी सरकार वर्ष 2025-26 में भी यह सुनिश्चित करेंगे कि करेगी की विभिन्न विभागों में पूर्व सैनिकों के लिए आरक्षित 15 प्रतिशत पदों को प्राथमिकता पर भरा जाए।

207. मैं सैनिक स्कूल में पढ़ रहे बच्चों के लिए प्रदेश सरकार द्वारा दिए जाने वाली डाइट मनी को 10 रुपये से बढ़कर 50 रुपये करने की घोषणा करता हूं। इस कदम का लक्ष्य यह है कि इन बच्चें को और विकसित सुविधाएं प्रदान की जा सकें। ढली में दिव्यांगों का एक

संस्थान है। मैं वहां गया था और मेरे साथ जनारथा जी भी गए थे। हमने वहां देखा कि वे बड़ी ठंड में रहते हैं चाहे वहां पर सेंट्रल हिटिंग भी उपलब्ध है। मैं उस संस्थान और उसमें लगे कर्मचारियों को सरकार के अधीन लेने की घोषणा करता हूं।

भर्तियां 208 एन0एस0 द्वारा ... शुरू
17-03-2025/1340/NS-AG/1

मुख्य मंत्री ----- जारी

भर्तियां

208. उच्च शिक्षा के क्षेत्र में सरकार द्वारा महाविद्यालयो/ विद्यालयों में विभिन्न श्रेणियां के कुल 1000 पद भरे जाएंगे। इसके अतिरिक्त विभिन्न श्रेणियां के लगभग 1000 कर्मियों को नियमित किया जाएगा। हमारी सरकार द्वारा वर्ष 2025-26 के दौरान राज्य में आयुष चिकित्सा पद्धतियों में सुधार के लिए आयुष चिकित्सा अधिकारियों के 200, होम्योपैथिक चिकित्सा अधिकारियों के 3, सोवा रिग्पा चिकित्सा अधिकारियों के 3, यूनानी चिकित्सा अधिकारियों के 2, आयुर्वैदिक फार्मेसी अधिकारियों के 52, लैब तकनीशियनों के 32, स्टाफ नर्सों के 33, ए0एन0एम0 के 82, जे0ओ0ए0 (आई0टी0) के 42 पदों को भरा जाएगा। पुलिस विभाग में पुलिस कांस्टेबलों के 1226 पदों को सीधी भर्ती के माध्यम से भरने की प्रक्रिया जारी है तथा बचे हुए 1000 रिक्त पदों की भर्ती प्रक्रिया वित्त वर्ष 2025-26 में फिर से आरंभ कर दी जाएगी। पुलिस कांस्टेबल की पदोन्नति से संबंधित बी0-1 परीक्षा लगभग 500 पदों हेतु करवाई जाएगी, इससे संबंधित अधिसूचना शीघ्र ही जारी की कर दी जाएगी। उक्त परीक्षा को वर्ष 2017 के बाद से अभी तक नहीं करवाया गया है। तकरीबन 8 साल बाद हम पुलिस विभाग में परीक्षा करवाने जा रहे हैं। सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश गृह रक्षा एवं नागरिक सुरक्षा विभाग में होमगार्ड स्वयं सेवक ड्राइवरों के 113 पदों को आगामी वित्त वर्ष में भरा जाएगा। राज्य सरकार द्वारा पंचायती राज संस्थाओं के कुशल एवं सुचारु संचालन के लिए आगामी वित्त वर्ष के दौरान पंचायत सचिवों के 853 पदों को सीधी भर्ती से, तकनीकी सहायकों के 219 पद भरे जाएंगे तथा कनिष्ठ अभियंताओं के 65 व सहायक अभियंताओं के 5 पद पदोन्नति से भरे जाएंगे। जल शक्ति विभाग में 4500 पैरा कर्मचारियों

जिनमें 2500 मल्टीपर्पस वर्कर, 1276 पैरा पंप ऑपरेटर, 500 पैरा फिटर, 92 पैरा कुक और 132 पैरा हैल्पर शामिल हैं, की नियुक्ति स्वीकृति प्रदान की गई है जिनकी नियुक्ति प्रक्रिया जारी है।

हमारी सरकार 2025-26 के दौरान उपर्युक्त पदों सहित लगभग 25000 लोगों को रोजगार प्रदान करेगी जिसमें 7000 आय के भी पद हैं और वोकेशनल टीचर्ज के पद शामिल हैं

17-03-2025/1340/NS-AG/2

विधायक प्राथमिकताएं

209. प्रत्येक वर्ष की भांति माननीय विधायकों के साथ हुई बैठकों के दौरान सामने आए सुझावों के आधार पर मैं निम्न घोषणाएं करता हूंः-

- विधायक प्राथमिकता योजना के अंतर्गत सभी माननीय विधायक अपनी प्राथमिकताओं में अपने विधानसभा चुनाव क्षेत्र से डे-बोर्डिंग स्कूल को भी सम्मिलित कर पाएंगे। यदि किसी पुरानी प्राथमिकता जिसकी अभी डी0पी0आर0 न बनी हो, को भी माननीय विधायक डे-बोर्डिंग स्कूल से सबस्टिच्यूट कर पाएंगे।
- मैं विधायक प्राथमिकता योजनाओं के प्रति विधानसभा चुनाव क्षेत्र की वर्तमान सीमा 195 करोड़ रुपये से बढ़ाकर 200 करोड़ रुपये करने की घोषणा करता हूं।

अध्यक्ष महोदय, वर्तमान कांग्रेस सरकार हमेशा से ही कर्मचारी हितैषी रही है। सत्ता में आते ही हमारी सरकार ने कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम शुरू करने के लिए पहली बैठक में निर्णय लिया। अभी भी हमारी सरकार पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में एन0पी0एस0 फिर से शुरू करने का दबाव बनाया जा रहा है।

आर0के0एस0 द्वारा ----- जारी

17.03.2025/1345/RKS/एजी-1

मैं इस माननीय सदन को आश्वासन दिलाना चाहता हूं कि इस दबाव का हल कर्मचारियों के साथ विचार-विमर्श करने के बाद निकाल लिया जाएगा।

कर्मचारी कल्याण

210. अध्यक्ष महोदय, हमारी सरकार यह मानती है कि प्रदेश के कर्मचारी सरकार की रीड की हड्डी है। पेंशनर्ज ने भी सेवाकाल के दौरान प्रदेश के विकास में अपना योगदान दिया है। परन्तु जब हमारी सरकार सत्ता में आई तो पिछली सरकार ने कर्मचारियों के वेतन एवं पेंशन आदि के लगभग 10 हजार करोड़ रुपये की एरियर की देनदारियां लंबित रखी थी।

211. मैं घोषणा करता हूं कि प्रथम चरण में 70 वर्ष से 75 वर्ष के आयु वर्ग के पेंशनरों के बकाया एरियर का भुगतान इस वित्तीय वर्ष में किया जाएगा। 15 मई से इस भुगतान की शुरूआत की जाएगी। इसी तरह चतुर्थ श्रेणी, तृतीय श्रेणी, द्वितीय श्रेणी तथा प्रथम श्रेणी के कर्मचारियों व अधिकारीयों को उनके बकाया वेतन एरियर का चरणबद्ध तरीके से भुगतान किया जाएगा। इससे कुल 1 लाख 75 हजार से अधिक कर्मचारियों एवं अधिकारियों को लाभ होगा। वेतन व पेंशन एरियर पर कुल 425 करोड़ रुपये खर्च किये जाएंगे।

212. अध्यक्ष महोदय, मुझे यह घोषणा करते हुए प्रसन्नता हो रही है कि प्रदेश के कर्मचारियों को 3 प्रतिशत की दर से मंहगाई भत्ते की किश्त 15 मई, 2025 से दी जाएगी।

213. हमने वित्तीय अनुशासन से अपनी वित्तीय स्थिति को ठीक किया है। आने वाले वर्ष में हमारी वित्तीय स्थिति चुनौती भरी है लेकिन हमने अपनी अर्थव्यवस्था में सुधार करते हुए आगे बढ़ने की कोशिश की है। कठिन वित्तीय स्थिति के बावजूद मैं निम्नलिखित घोषणाएं करता हूंः-

> दिहाड़ीदारों को 25 रुपये बढ़ोतरी के साथ 425 रुपये प्रतिदिन दिहाड़ी मिलेगी।

> आउटसोर्स कर्मियों को अब न्यूनतम 12,750 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

> हमारी सरकार का दृढ़ विश्वास है कि कर्मचारियों के सहयोग से प्रदेश की वित्तीय स्थिति में शीघ्र ही सुधार लाया जाएगा। मैं यह भी घोषण करता हूं कि हम आउटसोर्स की भर्तियों को धीरे-धीरे कम करके एक ऐसी योजना लाएंगे ताकि आउटसोर्स कर्मियों का शोषण न हो सके।

मानदेय वृद्धि

214. प्रदेश के विभिन्न विभागों में कार्यरत पैरा वर्कर्ज कई विकास योजनाओं के कार्यान्वयन में अहम भूमिका निभा रहे हैं। इन सभी के मानदेय की वृद्धि के लिए मैं निम्नलिखित घोषणा करता हूंः-

> आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को 500 रुपये की बढोतरी के साथ अब 10,500 रुपये मासिक मानदेय मिलेगा।

> मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं को मासिक 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ अब 7,300 रुपये मिलेंगे।

> आंगनवाड़ी सहायिका को प्रतिमाह 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ अब 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

> आशा वर्कर को 300 रुपये की बढ़ोतरी के साथ 5,800 रुपये प्रतिमाह मानदेय मिलेगा।

> सिलाई शिक्षकों के मासिक मानदेय को 500 रूपये बढ़ाया जाएगा।

> मिड डे मील वर्कर्ज को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,000 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

> वाटर कैरियर (शिक्षा विभाग) को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

> जल रक्षक को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

> जल शक्ति विभाग के Multi Purpose Workers को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 5,500 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।

श्री बी0एस0द्वारा... जारी

17.03.2025/1350/बी.एस./ए.एस/-1

मुख्य मंत्री जारी...

- लोक निर्माण विभाग के Multi Task Workers को 500 रुपये प्रतिमाह बढ़ोतरी की जाएगी।
- पैरा फिटर तथा पंप ऑपरेटर को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,600 रुपये प्रतिमाह मिलेंगे।
- पंचायत चौकीदार को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 8,500 रुपये प्रतिमा मिलेंगे।
- राजस्व चौकीदारों को 500 रुपये बढ़ोतरी के साथ 6,300 रुपए प्रतिमा मिलेंगे।
- राजस्व लंबरदार को 300 रुपये बढ़ोतरी के साथ 4500 रुपए प्रतिमा मिलेंगे।
- SMC अध्यापकों के मानदेय में 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी।
- IT Teachers को 500 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी।
  लेकिन हम जल्दी दोनों के टैस्ट करवा कर इन्हें जल्दी सरकार में लेने की कोशिश करेंगे।
- SPOs को 300 रुपये प्रति माह बढ़ोतरी की जाएगी।

बजट अनुमान

215 अध्यक्ष महोदय, अब मैं वर्ष 2024-25 के संशोधित हनुमानों पर आता हूं। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व प्राप्ति 43,704 करोड़ रुपए है। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार कुल राजस्व व्यय 50,190 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है। वर्ष 2024-25 के संशोधित अनुमानों के अनुसार 6,486 करोड़ रुपए का राजस्व डिफिसिट अनुमानित है।

216 अध्यक्ष महोदय, मैं वर्ष 2025-26 के लिए 58,514 करोड़ रुपये का बजट प्रस्तुत कर रहा हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं एक शेर सुनना चाहता हूं।

मैंने समंदर से सीखा है, जीने का सलीका,
मैंने समंदर से सीखा है, जीने का सलीका।
चुपचाप से बहना और अपनी मौज में रहना।

217 वर्ष 2025-26 में राजस्व प्राप्तियां 42, 343 करोड़ रुपए रहने का अनुमान है तथा कुल राजस्व व्यय 48,733 करोड़ अनुमानित है। इस प्रकार कुल राजस्व घाटा
17.03.2025/1350/बी.एस./ए.एस/-2

6,390 करोड़ रुपये अनुमानित है। राजकोषीय घाटा 10,338 करोड़ रुपए अनुमानित है जोकि प्रदेश के सकल घरेलू उत्पाद का 4.04 प्रतिशत है।

218 वर्ष 2025-26 के बजट अनुसार प्रति 100 रुपये में से वेतन पर 25 रुपये पेंशन पर 20 रुपये ब्याज अदायगी पर 12 रुपये, ऋण अदायगी पर 10 रुपये, स्वायत्त संस्थानों के लिए ग्रांट पर 09 रुपये, जबकि शेष 24 रुपए पूंजीगत कार्यों सहित अन्य गतिविधियों पर व्यय किए जाएंगे। अगले वर्ष के बजट का पूर्ण विवरण इस माननीय सदन में प्रस्तुत किए जा रहे विस्तृत बजट दस्तावेजों में उपलब्ध है। इसके अलावा FRBM Statement भी बजट के साथ प्रस्तुत की जारी है।

अध्यक्ष महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि जो पूर्व विधायक पिछले दिनों मुझे मिले थे, उनका कहना था कि उन्हें डी0ए0 नहीं मिलता। किसी कारणवश उनका डी0ए0 रुक गया। उनके डी0ए0 रुका नहीं क्योंकि नोटिफिकेशन में कुछ था। जो भी हमारे पूर्व विधायक हैं उन्हें पूरे डी0ए0 के साथ पेंशन मिलती है वह भी मिलेगी।

अध्यक्ष महोदय, मैं एक और शेर सुनना चाहता हूं,

अध्यक्ष : मुख्य मंत्री जी, एक-दो नहीं आप और अधिक शेर सुना सकते हैं।

हमें वक्त के साथ सोच को बदलना होगा और जो भविष्य की चुनौतियां हैं, हम अगर आज सोच नहीं बदलेंगे तो हम पिछड़ जाएंगे।

"परिवर्तन ही सृष्टि है, जीवन है,
स्थिर होना मृत्यु है,बेजान शांति मरण है।"

श्री दिवेश ठाकुर जारी.....

17.03.2025/1355/DT/AS/1

असूलों पर जहां आंच आए, टकराना जरूरी है,

जो जिंदा हो तो जिंदा नजर आना जरूरी है॥

अध्यक्ष महोदय, इस बजट अभिभाषण के मुख्य बिन्दु अनुबंध में दर्शाये गये हैं।

अध्यक्ष महोदय, इसी के साथ मैं यह बजट माननीय सदन के अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करता हूं।

जय हिन्द - जय हिमाचल

अध्यक्ष : अब इस माननीय सदन की बैठक मंगलवार 18 मार्च, 2025 के 11.00 बजे पूर्वाह्न तक स्थगित की जाती है।

दिनांक : 17.3.2025 **यशपाल शर्मा,**
शिमला : 171004. **सचिव।**